

# लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 325 ● भिलाई, शुक्रवार 10 जुलाई 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

## संक्षिप्त समाचार

उसने जो किया, उसकी सजा मिली, आरोपी की मां ने शव लेने से मना किया

**कोलकाता।** पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में हुए जघन्य बलात्कार और हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रभाष मंडल की मां ने ममता और संवेदना से ऊपर न्याय और नैतिकता को रखते हुए एक कड़ा फैसला लिया है। बुधवार को पुलिस मुठभेड़ (एनकाउंटर) में मारे गए अपने बेटे का शव लेने से उसकी मां ने साफ मना कर दिया है। उन्होंने दोटक शब्दों में कहा कि उनके बेटे ने जो धिनौना कृत्य किया था, उसकी सजा उसे मिलनी ही थी और वह ऐसे पापी का शव अपने घर नहीं लाएंगी। स्थानीय मीडिया से भावुक लेकिन बेहद सख्त लहजे में बात करते हुए आरोपी प्रभाष मंडल की मां ने सुबह के घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया सुबह जब मैं सोकर उठी ही थी, तब दो पुलिसवाले मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझे सूचना दी कि मेरा बेटा प्रभाष मर चुका है और मुझे सूचना दी कि उसका शव देखने या लेने अस्पताल चलना चाहूंगी।

**भरत तिवारी की मौत पर आयोग सख्त, पीड़ित परिवार को तुरंत मुआवजा देने का दिया आदेश**

**भोजपुर।** जिले के बेलौटी में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने प्रशासन के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा निर्देश जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया और विस्तृत जांच अपनी जगह है लेकिन मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मृतक के माता-पिता को तुरंत प्रभाव से अंतरिम मुआवजा प्रदान किया जाए। आयोग ने इस पूरी घटना को अत्यंत दुःख और गंभीर करार दिया है। एक युवा लड़के की जान जाने की लेकर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग ने कहा कि घटना की भयावहता को अंदाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही लगाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि भरत भूषण की मौत अत्यधिक रक्तस्राव और गोली लगने से उभरे सदमे के कारण हुई।

**कैलाश दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर, परमिट जारी होने में 2 माह की देरी**

**पिथौरागढ़।** तिब्बत में स्थित हिंदुओं के परम पावन कैलाश पर्वत के भारतीय सीमा से दर्शन करने की आस लगाए बैठे शिवभक्तों को अभी करीब दो महीने का लंबा इंतजार और करना होगा। वर्तमान में इस प्रतिबंधित सीमांत क्षेत्र के लिए जरूरी इन लाइन परमिट जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह रोक दिया गया है। स्थानीय जिला प्रशासन के मुताबिक, आगामी सितंबर महीने के आसपास जब यह परमिट दोबारा शुरू होंगे, तभी आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु समुद्र तल से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर मौजूद।

## ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी, सेल्फी डिप्लोमेसी में दिखी दोस्ती की झलक

# परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने का ऐतिहासिक अवसर है-पीएम

ऑस्ट्रेलिया/ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां उन्होंने इंडिया-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया अस्थिरता, सप्लाय चैन बाधा और ऊर्जा संकट से जूझ रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक और विश्वसनीय पार्टनर हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पीएम एंथनी अल्बानीज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने सेल्फी भी ली, जिसमें दोनों नेताओं की दोस्ती की झलक मिली। पीएम मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के विशाल यूरेनियम भंडार

और विशेषज्ञता भारत की परमाणु ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं के पूरक हैं। उन्होंने भारत के बंदरगाहों, हवाई अड्डों, सड़कों, रेलवे और शहरी अवसंरचना क्षेत्रों में दीर्घकालिक ऑस्ट्रेलियाई निवेश को आमंत्रित करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की प्रौद्योगिकी, पूंजी और संसाधन भारत के विकास पथ को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, लोकतांत्रिक मूल्यों और हिंदू प्रशांत महासागर में रणनीति के लिए दोनों देशों का साझा विजन है। हम अपनी व्यापारिक साझेदारी को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। इसमें आप लोगों (सीईओ) की भूमिका अहम है और मुझे विश्वास है कि ये बैठक नए विचारों, नई साझेदारी को जन्म देगी। कुछ समय पहले भारत ने SHANTI Act से न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों



के लिए खोल दिया है। हमने 2047 तक 100 जीडब्ल्यू परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया के विशाल यूरेनियम रिजर्व भारत को न्यूक्लियर यात्रा से सीधे रूप से जुड़ते हैं। हमारे लिए इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक अवसर है। इंडिया-ऑस्ट्रेलिया सीईओ

फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने साल 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमारे रान्यों छोटे-बड़े शहरों

और विश्वविद्यालयों आदि सभी को इस विकास गाथा में हिस्सेदार बनना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, ऑस्ट्रेलिया आज 4 खरब डॉलर के पेंशन फंड मैनेज करता है। भारत में पेंशन को प्रिवेटा के साथ देखा जाता है और यह करोड़ों लोगों के विश्वास को दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया के ये पेंशन फंड भारत की विकास गाथा से लाभान्वित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया अस्थिरता, सप्लाय चैन बाधा और ऊर्जा संकट से जूझ रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक और विश्वसनीय पार्टनर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में दोनों देशों ने भावी साझेदारी का एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। 2022 में रिकॉर्ड समय में ईसीटीए समझौता किया गया, जिससे हमारी आर्थिक साझेदारी और मजबूत हुई।

**क्रिकेट जैसा मजबूत है भारत-ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता-पीएम मोदी**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को क्रिकेट से जोड़ते हुए कहा कि दोनों देशों की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की मुलाकातें क्रिकेट की तरह होती हैं- एजेंडा वरुडे की तरह फ्लोरड, फैसले टी-20 की तरह तेज और साझेदारी टैरट मैच की तरह लंबी व भरपूर है। ऑस्ट्रेलिया के आतंकवाद को पूरी मान्यता के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया इस दुनिया के खिलाफफुट हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों की लड़ाई साझा है और सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि अब तक दोनों देशों की रूढ़िवादी वैन तो जुड़ी हुई थी, लेकिन नीतिगत स्तर पर कुछ अंतर बने हुए थे।

## एबीवीपी के 78 वें स्थापना दिवस

# राष्ट्र सर्वोपरि, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म... सीएम रेखा गुप्ता

**नई दिल्ली।** दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर संगठन के कार्यकर्ताओं और छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं। रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हेंडल पर पोस्ट करके कहा है कि कुछ ऋण जीवन भर चुकाए नहीं जाते, केवल अपने कर्मों से निभाए जाते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ऋण मेरे जीवन पर ऐसा ही है। एबीवीपी ने मुझे राष्ट्रसेवा के संस्कार दिए, जीवन का उद्देश्य दिया। यहीं सीखा कि



राष्ट्र सर्वोपरि है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और कार्यकर्ता का सबसे बड़ा परिचय उसके पद से नहीं, उसके समर्पण से होता है। उन्होंने आगे कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुई मेरी यात्रा को विद्यार्थी परिषद ने दिशा दी।



पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की के कथित रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी प्रभाष मंडल की फाइल फोटो। पुलिस ने बताया कि बाद में क्राइम सीन को फिर से बनाने (री-कंस्ट्रक्शन) के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मंडल की मौत हो गई।

## सरकार ने श्रीराम की मर्यादा तोड़ी

# मंदिर में 99.9 प्रतिशत लोग बीजेपी से जुड़े....

**नई दिल्ली।** उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में सुबे में राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म, गौ संरक्षण और प्रदेश में कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। शंकराचार्य से हुई मुलाकात को अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट करते हुए इसे सनातन पर आए संकट को दूर



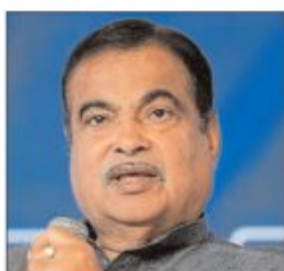
करने व अधर्मियों के चंगुल से धर्म को मुक्ति दिलाने के लिए सार्थक वार्ता बताया। शंकराचार्य से मुलाकात के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला।

## ई20 पेट्रोल को लेकर गडकरी ने किया दावा

# माइलेज पर मामूली असर होगा इंजन पर नहीं-नितिन गडकरी...

नई दिल्ली/ एजेंसी

पेट्रोल में एथनॉल मिलाने को लेकर इस समय देश भर के आम आम नागरिकों के मन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या वाकई पेट्रोल में एथनॉल मिलाने से गाड़ियां खरब हो रही हैं और माइलेज पर क्या असर पड़ रहा है। अब इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम ऊर्जा होती है। नितिन गडकरी ने कहा कि जब पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा बढ़ती है, तो गाड़ी का औसत माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। नितिन गडकरी ने कहा कि ये फर्क बहुत



मामूली होता है। नितिन गडकरी का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैल रही ई20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान की बातों में सच्चाई नहीं है। उन्होंने इन दावों को भ्रमक बताया और कहा कि उन्हें बड़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि ई20 पेट्रोल को पूरे देश में लागू करने से

पहले इसको लेकर कई तरह के टेस्ट हुए थे। उन्होंने बताया कि ये टेस्ट पुणे स्थित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और वाहन बनाने वाली कंपनियों द्वारा किए गए थे। उन्होंने बताया कि सभी जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही ई20 पेट्रोल पूरे देश में शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वाहन बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि पुरानी कारों में अगर सर्विस के दौरान पुर्जे बदलने की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें बदल दिया जाए। नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे एक भी ऐसी गाड़ी दिखाएँ जिसे ई20 पेट्रोल की वजह से नुकसान हुआ हो।

## स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारत आ रहे एलपीजी टैंकर पर ड्रोन से हमला

नई दिल्ली।

होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। भारत आ रहे कतर के एक एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) से लदे जहाज पर संदिग्ध ड्रोन से हमला किया गया है। एलएनजीसी अल रेकय्यात नामक यह जहाज कतर के दहेज बंदरगाह से गुजरत के दहेज बंदरगाह की ओर जा रहा था, तभी इसे निशाना बनाया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई, जिससे भारी धुआं उठने लगा। हालांकि, किसी के हताहत होने या गैस रिसाव की सूचना नहीं है। जहाज पर कुल 29 चालक दल के सदस्य सवार हैं, जिनमें चार भारतीय नाविक भी शामिल हैं।

## तीनों ने राज्यसभा से दिया था इस्तीफा

# बीजेपी में शामिल हुए सुखेंदु सुष्मिता और प्रकाश बड़ाईक

नई दिल्ली/ एजेंसी

तृणमूल कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है क्योंकि पिछले महीने राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले उनके तीनों सांसदों ने अब भाजपा का दामन धाम लिया है। पूर्व सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बड़ाईक आज (गुरुवार, 9 जुलाई को) पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के सामने पार्टी में शामिल हो गए। भट्टाचार्य ने पार्टी के साल्ट लेक ऑफिस में आयोजित एक



कार्यक्रम में, जिसमें राज्य के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, पूर्व सांसदों को बीजेपी का झंडा देकर और पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद, देव, राय और बड़ाईक ने पिछले महीने

राज्यसभा और तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। राय और बड़ाईक का कार्यकाल सितंबर 2029 तक था, जबकि देव का कार्यकाल अप्रैल 2030 तक चलना था। इन तीन सीटों के लिए उपचुनाव 24 जुलाई को होने हैं और बीजेपी के तीनों सीटें जीतने की उम्मीद है। इस मौके पर समिक भट्टाचार्य ने कहा कि इन तीन पूर्व सांसदों का अनुभव राज्य में पार्टी को और मजबूत करेगा। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद, बीजेपी 294 सदस्यों वाली विधानसभा में 208 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है।

## छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

# पहली कक्षा में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय

रायपुर। संवाददाता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी विद्यालयों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रतीत सिंह ने संबंधित विभागों और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। भौगोलिकसंदर्भस्कूल शिक्षा सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बच्चों के फंडेशनल स्टेज को मजबूत करने और प्राथमिक स्तर पर

प्रवेश प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए संबंधित शैक्षणिक सत्र के 01 अप्रैल को बच्चों की आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित आयु सीमा इस प्रकार होगी- नर्सरी (बालवाटिका-1): 3 वर्ष से अधिक एवं 4 वर्ष से कम। केजी-1 (बालवाटिका-2): 4 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष से कम। केजी-2 (बालवाटिका-3): 5 वर्ष से अधिक एवं 6 वर्ष से कम। कक्षा पहली: 6 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष से कम। अभिभावकों और बच्चों की सुविधा के लिए शासन ने नियमों में थोड़ी शिथिलता भी दी है। इसके तहत यदि कोई बच्चा 01 अप्रैल को निर्धारित आयु पूरी नहीं कर पा रहा है, लेकिन 01 जुलाई तक उसकी आवश्यक आयु पूर्ण हो जाती है,



तो उसे अधिकतम तीन माह की छूट प्रदान करते हुए संबंधित कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा। समय और कैलेंडर यह नई व्यवस्था राज्य के सभी शासकीय, अशासकीय (निजी) और अनुदान प्राप्त

विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगी। साथ ही, शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर होने वाले प्रवेशों पर भी यह नियम पूरी तरह प्रभावी रहेगा। विभागीय

निर्देशों के अनुसार, यदि कोई छात्र किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय की पूर्व-प्राथमिक कक्षा से पास होकर (प्रोजेक्ट होकर) सीधे कक्षा पहली में प्रवेश ले रहा है, तो उस पर यह नई आयु सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे छात्रों को उनके स्थानांतरण प्रमाण-पत्रअंकसूची या स्कोर कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर ही प्रवेश दे दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, संकुल समन्वयकों और सभी शाला प्रमुखों के माध्यम से इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही, अभिभावकों की जानकारी और सुविधा के लिए इन नए प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

**अब 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश**

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र अब हर वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक चलाया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रतीत सिंह ने संवत्सव, लोक शिक्षा संवत्सव को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार का यह निर्णय देश के अन्य प्रमुख शिक्षा सत्र की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब तक प्रदेश में स्कूलों का शैक्षणिक सत्र 16 जून से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल तक चलता था।



**स्याही सूखी तो खून से लिखा आवेदन: दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का संविलियन आंदोलन तेज**

दुर्ग। संविलियन की मांग को लेकर जिला मुख्यालय स्थित जेआरडी स्कूल और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदेशभर के अतिथि शिक्षकों का अनिश्चितकालीन आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आंदोलनकारी नित नए तरीके अपना रहे हैं, जिसके तहत कुछ दिन पूर्व एक पैर पर खड़े होकर विरोध जताने के बाद गुरुवार को शिक्षकों ने अपने खून से आवेदन लिखकर नाराजगी जाहिर की। फोटो: नाहीद शेष

**कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में वन महोत्सव के आयोजन के तैयारियों की समीक्षा की**

**समाज के सभी वर्गों से अधिक से अधिक पौधरोपण कर वृहद वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के लिए निर्देश**



बालोद। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने अधिकारियों की बैठक लेकर वनमहोत्सव के अवसर पर जिले में वृहद वृक्षारोपण अभियान के तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को वृहद वृक्षारोपण कार्य में समाज के सभी वर्गों के लोगों को सहभागिता सुनिश्चित

कराया। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में वनमण्डलाधिकारी अभिषेक चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर चंद्रकांत अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी सुनील अधिकारीगण उपस्थित थे।

**2.39 लाख सीपीटी ट्रेच पर सीड बॉल का किया जाएगा रोपण**

बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों से अधिक पौधरोपण हेतु पौधों की उपलब्धता एवं ट्रेच निर्माण आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। उन्होंने इस कार्य में महिला एवं ग्राम कमाण्डो, एनसीसी एवं एनएसएस के विद्यार्थियों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों को सहभागिता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले में वन महोत्सव के आयोजन की तिथि शीघ्र ही निर्धारित किया जाएगा। मिश्रा ने बालोद जिले को हथ-भरा बनाने जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई मिशन अंकुर के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत जिले के डीएचडी ब्लॉक के गुनरा ग्राम पंचायत के ग्राम पंडवाल में आगामी 13 जुलाई को सीड बॉल रोपण हेतु जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ग्राम पंडवाल सहित सीड बॉल रोपण हेतु जिले के विभिन्न स्थानों पर बनाए गए कुल 2 लाख 39 हजार सीपीटी ट्रेच पर सीड बॉल का रोपण किया जाएगा। इस दौरान सीड बॉल को सीपीटी ट्रेच के दोनों किनारों में फैले मिट्टी में दबाकर इसका रोपण किया जाएगा।

**सफल आयोजन हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश**

कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने मिशन अंकुर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सीड बॉल मिट्टी, खाद और विभिन्न उपयोगी वृक्षों के बीजों को मिलाकर बनाई गई एक छोटी सी गेंद होती है। इसे रोपने के लिए गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं होती। इसे हार्ड ट्रेच, जंगल, खाली जमीनों, पहाड़ियों या बंजर इलाकों में फेंक दिया जाता है। मानसून की बारिश पड़ते ही यह अंकुरित होकर एक पौधे का रूप ले लेती है। मिशन अंकुर के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रजातियां जैसे- नीम, पीपल, बरगद, मुन्गा, करंज, कटहल, इमली आदि के बीजों का उपयोग कर सीड बॉल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 13 जुलाई को मिशन अंकुर के सफल आयोजन हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

**वन महोत्सव पर कृषि महाविद्यालय बेमेतरा में हुआ व्यापक वृक्षारोपण**

बेमेतरा। वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं हरित वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेवेन्द्र सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, ढोलिया (बेमेतरा) में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तत्वावधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें महाविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर अधिष्ठाता डॉ. अनूप कुमार सिंह ने कहा कि पेड़-पौधे मानव जीवन के आधार हैं। वृक्ष न केवल हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनका संरक्षण करने का



संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि केवल पौधारोपण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण करना भी प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधे का रोपण कर उसका संरक्षण सुनिश्चित करे, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, छात्र-छात्राओं, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों ने महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सभी प्रतिभागियों ने वृक्षों की नियमित देखभाल करने तथा अधिक से अधिक लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर डॉ. यू. के. फ़व, डॉ. अमित कुमार, कुती बंजारे, डॉ. भारती बघेल, डॉ. हेमलता निराला, डॉ. प्रीति पैकर, डॉ. सश्री बजाज, प्रतिभा सिंह, डॉ. सरिता शर्मा, डॉ. महानंद, डॉ. रामेश्वर, संजीव गुर्जर सहित महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। महाविद्यालय प्रशासन ने बताया कि वन महोत्सव के अंतर्गत भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित हो और हरित एवं स्वच्छ वातावरण के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

**यूथ हॉस्टल द्वारा पोटियाडीह में किया गया वृक्षारोपण**

धमतरी। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की धमतरी इकाई द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित धमतरी अभियान के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल पोतियाडीह में यूथ एवं इको क्लब के सहयोग से सघन वृक्षारोपण एवं सीड बॉल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में लगभग 60 छायादार एवं फलदार पौधों का रोपण किया गया तथा विद्यार्थियों को पौधों के संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। ये न केवल शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि जल संरक्षण एवं जलवायु संतुलन एवं जैव विविधता के संरक्षण तथा ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी विद्यार्थियों से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का आग्रह



किया गया। कार्यक्रम के दौरान यूथ एवं इको क्लब प्रभारी गीतांजलि साहू एवं विद्यार्थियों द्वारा बड़ी संख्या में सीड बॉल यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, धमतरी इकाई को प्रदान किए गए जिनका उपयोग वर्षा ऋतु में विभिन्न क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के लिए किया जाएगा। कार्यक्रम में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, धमतरी के अध्यक्ष सुदीप सिंह, अध्यक्ष रमेश देव, सचिव सुबोध महावर, पूर्व चेयरमैन योगेश गुप्ता, डॉ. भूपेंद्र सोनी, डॉ. धर्मेन्द्र सिन्हा, विश्वेश कोटवानी एवं परिवर्तन कौर गिल की विशेष सहभागिता रही। विद्यालय की प्राचार्य चंपा चंद्राकर ने सभी अतिथियों का स्वागत करते

**यादव महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने जनगणना आयुक्त से की मुलाकात**



सरायपाली। नई दिल्ली में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने जनगणना भवन में भारत के महाराजस्ट्र एवं जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से मुलाकात कर यादवों की सभी उपजातियों में कालम कर जाति जनगणना करने की मांग की। सत्य प्रकाश सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आनंद प्रकाश मुख्य महासचिव, गोरालाल यादव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, रणवीर सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिनेश यादव राष्ट्रीय महासचिव, प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। जाति जनगणना 2027 में आपके घर आंवद प्रणाली को जाति के कालम में यादव ही दर्ज करवाना है चाहे राज्यों में प्रचलित उपजातियां कुछ भी हों। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के समस्त पदाधिकारियों व सम्मानित कार्यकर्ताओं के समर्थ सह जुनौती पूर्ण अभियान है। हमें विश्वास है कि जिस उत्साह से हमने रेजांगला कलश यात्रा अहीर रेजिमेंट की मांग पर पोस्टकार्ड अभियान व जिला स्तर पर प्रदर्शन जैसे विशाल कार्यक्रम आयोजित किए। अब उससे भी अधिक मेहनत से यहां जन जागरण कार्यवाही गांव-गांव तक पहुंचाना है और देश के प्रत्येक यादवों को इस महत्वकांक्षी अभियान से जोड़कर जाति जनगणना में सिर्फ यादव जाति ही रिकॉर्ड में दर्ज करवा कर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या का गौरव प्राप्त करना है। इंजीनियर एस टी यादव राष्ट्रीय सचिव, भुनेश्वर यादव

**पारधी गिरोह के 7 शातिर चोर गिरफ्तार, 12.46 लाख की संपत्ति बरामद**



सरायपाली। थाना सिंसोड़ा क्षेत्र में हुई नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए पारधी गिरोह के सात शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने-चांदी के आभूषण, तीन मोटरसाइकिल सहित कुल 12 लाख 46 हजार रुपये की संपत्ति बरामद की है। मामले में चोरी का माल खरीदने वाले एक व्यक्ति की भी भूमिका सामने आई है। पुलिस के अनुसार 23 जून को ग्राम रुद्र निवासी हरिश्चंद्र पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 जून की रात अज्ञात चोर उनके घर में घुसकर अलमारी उड़कर खेत में ले गए और उसे तोड़कर उसमें रखी नकदी, सोने के आभूषण तथा चांदी के पायल चोरी कर फरार हो गए। शिकायत पर थाना सिंसोड़ा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों के कार्य करने के तरीके (मोडस ऑपरेण्डे) का अध्ययन किया। जांच में पता चला कि घटना से एक दिन पहले आरोपी ग्राम पैकिन में एक छतरी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सीसीटीवी फुटेज और पुछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। पुछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात स्वीकार करते हुए बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने आसपास के गांव में चोरी करने की योजना बनाई थी। रात में ग्राम रुद्र के एक मकान से अलमारी उड़कर खेत में ले जाकर उसमें रखी नकदी और आभूषण चोरी कर लिए। नकदी आपस में बांट ली गई, जबकि सोने के आभूषण रायपुर निवासी एक ज्वेलर्स को बेच दिए गए।

**डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए कृषकों से 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित**

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने एवं सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस संबंध में जिले के कृषकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कृषक कृषि उपसंचालक कार्यालय से आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म 31 जुलाई 2026 तक फार्म कार्यालय में जमा कर सकते हैं। 31 जुलाई 2026 के निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक कृषक जो खेती में नवाचार, जैविक कृषि, उत्पादन में वृद्धि, कृषि यांत्रिकीकरण या जल संरक्षण

जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। वे इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिले के समस्त पात्र कृषकों से अपील किया गया है कि वे निर्धारित तिथि तक आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक अर्हताएं एवं अन्य जानकारी कृषि कार्यालयों या जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं कृषक नेता डॉ. खूबचंद बघेल के नाम पर दिया जाता है, जिनके योगदान को याद करते हुए यह सम्मान उन कृषकों को दिया जाता है, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बनी है।

**स्थगन आदेश के बाद भी निर्माण कार्य होने से उठे सवाल, शासकीय भूमि पर हो रहा अवैध निर्माण**

धमतरी। जिले में जबसे कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने पदभार संभाला है, तबसे लेकर अब तक केंद्र एवं राज्य सरकार के योजनाओं का जिले के आंखि छोर तक बैठे व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। अपने एक बर्षीय कार्यकाल में उन्होंने जिले की लॉक और बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करने में सफलता पाई है। लेकिन उनके अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा कुछ मामलों में लापरवाही बतकर उनके स्वच्छ प्रशासन पर ग्रहण लगाने का कार्य किया जा रहा है। ताजा मामला डेंजर जेन में बनने वाले रिसॉर्ट से दिया जा सकता है जहां फिखले दिनों राजस्व अमला द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर स्थान आदेश जारी किया गया था। लेकिन खबर के मुताबिक स्थगन आदेश के बाद भी उक्त स्थल पर सुबह 5 बजे से 8 बजे तक निर्माण कार्य की जानकारी इस प्रतिनिधि को मिली है जिससे अधिनस्थ अधिकारियों के रवैये पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं। रिवंशकर सागर परियोजना गंगरेल से निकट ग्राम कोटामरी के क्षेत्र में शासकीय भूमि के बहुत बड़े भूभाग पर अतिक्रमण कर वहां रिसॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है। बिना अनुमति के होने



वाले इस कार्य को लेकर जब कलेक्टर को इसकी शिकायत प्राप्त हुई तो उन्होंने वहां राजस्व अमला को स्थल मुआयना के लिये भेजा जहां रिसॉर्ट का कार्य होना पाया गया और निर्माण कार्य को रोकने के लिये स्थगन आदेश जारी किया गया। लेकिन उक्त स्थल पर निर्माण कार्य सुबह 5 बजे से 8 बजे तक किये जाने की जानकारी मिली है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी राजस्व अधिकारियों को नहीं है। लेकिन वे मुकदरस की तरह उक्त कार्य को पूर्णता की ओर ले जाने के लिये अप्रत्यक्ष रूप से उक्त व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे हैं जबकि जिले के

उक्त व्यक्ति द्वारा घोर उल्लंघन किया जा रहा है। गंगरेल बांध के नीचे स्थित ग्राम कोटामरी क्षेत्र में बन रहे इस रिसॉर्ट का यह क्षेत्र विभागीय अधिकारियों में डेंजर जेन के नाम से दर्ज है। तत्कालीन कार्यपालन अधिन्याय ओ पी राठी ने वर्ष 1980 में गंगरेल बांध के नीचे से लेकर ग्राम कोटामरी तक के हिस्से को खतरे का क्षेत्र माना था क्योंकि इस अवधि में बाढ़ आई थी और गंगरेल से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था जिससे बरारी का ऊपर पारा तक यह पानी पहुंचा था। उस समय फसलों को नुकसान पहुंचा था और दो मवेशियों की मौत हो गई थी और पुराना गंगरेल बाजार में रहने वाले एवं दुकान चलाने वाले लोगों की दुकानें, मकान आदि पूरा इसकी चोट में आया था। कोटामरी क्षेत्र, गंगरेल के समीप होने की वजह से इस जगह पर रिसॉर्ट का निर्माण बिना अनुमति के किया जा रहा है। यदि यह रिसॉर्ट का निर्माण राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा बनाने से नहीं रोका गया तो आने वाले समय में इस रिसॉर्ट में रहने वाले लोगों को भयंकर दुर्घटना से होकर गुजरना पड़ सकता है और जान माल की हानि भी हो सकती है। सबसे

संक्षिप्त समाचार

बिना लाइसेंस खाद बेचने पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई

रायपुर। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध विक्रय पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जशपुर जिले में कृषि विभाग द्वारा लगातार सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड बगोचा के ग्राम चम्पा में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध लाइसेंस एवं दस्तावेज के भंडारित 141 बोरो उर्वरक जब्त कर उसके विक्रय पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया। उप संचालक कृषि श्री एम.आर. भगत ने बताया कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री लालसाय केरकेट्टा, कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक श्रीमती कुरुसलीना मिंज तथा संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की संयुक्त टीम ने ग्राम चम्पा में श्री नईम अख्तर के निवास पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 25 बोरो डीएपी, 10 बोरो एसएसपी तथा 106 बोरो यूरिया सहित कुल 141 बोरो उर्वरक बिना किसी वैध बिल अथवा दस्तावेज के भंडारित पाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना वैध उर्वरक लाइसेंस के खाद का विक्रय किया जा रहा था। आवश्यक दस्तावेज एवं लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कृषि विभाग ने उर्वरक निर्यात आदेश के तहत संपूर्ण उर्वरक जब्त कर सुपरनामा तैयार किया तथा उसके विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। कृषि विभाग ने बताया कि प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देश पर जिले के सभी विकासखंडों में जिला स्तरीय टीम द्वारा उर्वरक विक्रय केंद्रों एवं भंडारण स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य कालाबाजारी, जमाखोरी, नकली उर्वरकों की बिक्री तथा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय जैसी अनियमितताओं पर प्रभावी निर्यात सुनिश्चित करना है।

पक्का घर और सम्मानजनक सहयोग से संवर रहा झगरीबाई का जीवन

रायपुर। शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना एवं महतारी वंदन योजना ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के साथ उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सको जिले की ग्राम पंचायत रायपुर निवासी श्रीमती झगरीबाई इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर अपने परिवार के बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें पक्के आवास की स्वीकृति मिली है, जिसका निर्माण कार्य अब पूर्णता की ओर है। वहीं महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली सहायता राशि से उन्हें घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में आर्थिक संबल मिल रहा है। श्रीमती झगरीबाई ने बताया कि पहले उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था। बरसात के दिनों में घर की छत से पानी टपकने सहित अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण पक्का मकान बनाना संभव नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से अब उनका पक्का घर तैयार होने की अंतिम अवस्था में है। उन्होंने कहा कि नया आवास बनने से उनके परिवार को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध होगा तथा बरसात सहित अन्य मौसम संबंधी परेशानियों से भी राहत मिलेगी। श्रीमती झगरीबाई ने बताया कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह प्राप्त होने वाली सहायता राशि से वे घर की आवश्यक जरूरतों की पूर्ति कर रही हैं। इस राशि से आवश्यक घरेलू सामग्री खरीदने में सुविधा मिल रही है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली है।

मोर गांव मोर पानी अभियान बना जल संरक्षण की नई राह

रायपुर। विकसित भारत ग्रांटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में संचालित मोर गांव मोर पानी अभियान जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए ग्रामीण विकास का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। अभियान के तहत जिले में 350 आजीविका डबेरियों तथा 150 से अधिक सामुदायिक तालाबों का निर्माण, गहरीकरण एवं विकास किया गया है। इन कार्यों से वर्षा जल के संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिलने लगी है। जिले में मानसून के दौरान प्राप्त होने वाले वर्षा जल का अधिकतम संचयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्मित इन जल संरचनाओं से अब जल संरक्षण के सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। आजीविका डबेरियां एवं सामुदायिक तालाब जल को संरक्षित कर भू-जल स्तर में वृद्धि करने के साथ-साथ खेतों में सिंचाई को उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे किसानों को खेती के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा तथा फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अभियान के अंतर्गत निर्मित 350 आजीविका डबेरियां ग्रामीण परिवारों के लिए आय के नए अवसर भी सुनिश्चित करेंगी। इन डबेरियों का उपयोग मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन, उद्यानिकी, पशुपालन तथा अन्य आजीविका गतिविधियों में किया जा सकेगा।

एसडीजी 2.0 और बस्तर अंजोर से विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री साय ने किया छत्तीसगढ़ एसडीजी 2.0 फ्रेमवर्क का विमोचन

■ बस्तर के समग्र एवं परिणामोन्मुख विकास के लिए 'बस्तर अंजोर' पहल का शुभारंभ

■ राज्य स्तर पर 343 और जिला स्तर पर 99 संकेतकों के माध्यम से होगी विकास कार्यों की प्रभावी निगरानी

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की उपस्थिति में राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. 2.0 फ्रेमवर्क का विमोचन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. राज्य एवं जिला संकेतक प्रेमवर्क 2.0 तथा मेटाडेटा हैंडबुक का भी



विमोचन किया गया। साथ ही बस्तर संभाग के समावेशी, अभिसरण आधारित और मापनीय विकास के लिए तैयार की गई अभिनव पहल 'बस्तर अंजोर' की भी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, सटीक डेटा और परिणाम आधारित मॉनिटरिंग अत्यंत आवश्यक है। एस.डी.जी. 2.0 फ्रेमवर्क शासन को साध्य-आधारित नीति निर्माण, बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय तथा योजनाओं की नियमित निगरानी के लिए एक सशक्त

आधार प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल 'विकसित छत्तीसगढ़ 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल विकास साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, सटीक डेटा और परिणाम आधारित मॉनिटरिंग अत्यंत आवश्यक है। एस.डी.जी. 2.0 फ्रेमवर्क शासन को साध्य-आधारित नीति निर्माण, बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय तथा योजनाओं की नियमित निगरानी के लिए एक सशक्त

स्तर पर 82 से बढ़ाकर 99 कर दी गई है। इससे विकास कार्यों की अधिक व्यापक, सटीक और वैज्ञानिक निगरानी संभव होगी। मेटाडेटा हैंडबुक में प्रत्येक संकेतक की गणना पद्धति एवं रिपोर्टिंग प्रणाली को मानकीकृत किया गया है, जिससे पूरे राज्य में डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने 'बस्तर अंजोर' की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह अभिसरण (कन्वर्जेंस) आधारित विकास मॉडल है, जिसे बस्तर संभाग को देश का सर्वाधिक विकसित जनजातीय क्षेत्र बनाने के संकल्प को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि 'बस्तर अंजोर' के 3+4 मॉडल के अंतर्गत जिला स्तर की तीन प्रमुख पहल - नियद नेम्बनार 2.0, बस्तर मुझे और स्वस्थ बस्तर - का अभिसरण चार प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विकास प्रेमवर्क - एस.डी.जी. 2030, विकसित छत्तीसगढ़ 2047, आकांक्षी जिला एवं विकासखंड कार्यक्रम से किया गया है।

बिहान योजना से महिलाओं को मिल रही आत्मनिर्भरता की एक नई दिशा

■ 6 लाख रुपये के ऋण से पशुपालन, मिक्सचर मशीन एवं सेटरिंग व्यवसाय का कर रही विस्तार

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ शासन की बिहान योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी साबित हो रही है। योजना के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों को स्वरोजगार एवं आजीविका संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर परिवार को आय में वृद्धि कर रही हैं। इसी क्रम में सको जिले के ग्राम रायपुरा की विकास समिति महिला स्व-सहायता समूह को विभिन्न आजीविका गतिविधियों के विस्तार हेतु 6 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया गया है। समूह की सदस्य श्रीमती दिलेश्वरी सिदार एवं अन्य महिलाओं

ने बताया कि ऋण राशि का उपयोग पशुपालन, मिक्सचर मशीन तथा सेटरिंग सामग्री क्रय करने में किया गया है। इन गतिविधियों के माध्यम से समूह की आय में वृद्धि होने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सुनिश्चित होंगे। उन्होंने बताया कि इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि परिवार की आवश्यकताओं को पूर्णतः भी पहले से बेहतर ढंग से हो सकेगा। महिलाओं ने कहा कि बिहान योजना से प्राप्त वित्तीय सहायता उनके लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सहयोग से उन्हें अपने स्वरोजगार कार्यों का विस्तार करने का अवसर मिला है और भविष्य में आय बढ़ाने के नए मार्ग भी खुल रहे हैं। समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनने की नई दिशा प्रदान कर रही हैं।

रेलवे ओवर-ब्रिज एवं रेलवे अंडर ब्रिज कार्यों की समीक्षा संपन्न हुआ

■ कार्यस्थलों में आ रहे अवरोधों को तत्परता से दूर कर अप्रारंभ कार्यों को जल्दी शुरू करने कहा

रायपुर/ संवाददाता

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने विभाग के सेतु परिक्षेत्र और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश में रेलवे ओवर-ब्रिज और रेलवे अंडर-ब्रिज के निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आज हुई बैठक में रेलवे ओवर-ब्रिज और रेलवे अंडर-ब्रिज के कार्यों में तेजी लाने लोक निर्माण विभाग और रेलवे के अधिकारियों को बेहतर समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यस्थलों की बाधाओं को तत्परता से दूर कर अप्रारंभ

कार्यों को जल्दी शुरू करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भट्टपहरी और दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के बिलासपुर मुख्यालय के प्रधान मुख्य अभियंता श्री अनवीश कुमार पाण्डेय भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में विभागीय और रेलवे के अधिकारियों को आपसी समन्वय को और मजबूत करते हुए निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें शीघ्र पूरा करने को कहा, ताकि लोगों को जाम और रेलवे फटकों पर होने वाली असुविधा से राहत मिल सके। इससे माल परिवहन भी अधिक सुगम और तेज होगा। विभागीय सचिव ने नए आरओबी और आरयूबी के कार्यों को जल्द शुरू करने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर बाधाओं का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।



बिहान योजना से महिलाओं को मिल रही आत्मनिर्भरता की एक नई दिशा.....

आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध वनवासियों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता-मंत्री केदार कश्यप

रायपुर/ संवाददाता



विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार तेन्दूपता संग्रहकों, वनवासियों और आदिवासी परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगल से जुड़े प्रत्येक श्रमिक को उसके श्रम का उचित

सम्मान मिले और पारिश्रमिक समय पर सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचे। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने बताया कि विगत 3 जुलाई को सहकारिता सप्ताह एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा वर्ष 2023 के तेन्दूपता संग्रहण के प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण का शुभारंभ किया गया। इसके तहत प्रदेश की 621 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों से जुड़े 7,14,446 तेन्दूपता संग्रहकों को 162.32 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट बेंचिनिष्ठ ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है।

सुशासन तिहार बना दिव्यांगजनों के लिए उम्मीद की नई राह तीन को मिला सहायक उपकरण

रायपुर। शासन की जनहितकारी पहल सुशासन तिहार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रही है। इसी पहल के तहत समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों के आवेदनों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण करते हुए उन्हें आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए। कोण्डागांव जिले के विकासखंड माकड़ी के ग्राम पंचायत मगोदा निवासी श्री हौरू राम ने सुशासन तिहार के दौरान मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन प्राप्त होने के बाद समाज कल्याण विभाग ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उन्हें आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला कार्यालय में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया। प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त उन्हें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान की गई, जिससे अब उनका आवागमन पहले की तुलना में कहीं अधिक सहज और आत्मनिर्भर हुआ है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बिराकसा के श्री गणेश तथा ग्राम पंचायत कुरदुबहार के श्री दयनु राम नेताम को उनकी आवश्यकता के अनुरूप स्मार्ट केन उपलब्ध कराई गई।

समय पर खाद, बीज और ऋण से खुशहाल हुई खेती

■ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की किसान हितैषी पहल से किसान सोमारु की राह हुई आसान

रायपुर। संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसानों को समय पर कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में देखने को मिल रहा है। खरीफ सीजन से पहले जिला प्रशासन ने किसानों को खाद, उन्नत बीज और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ऋण समय पर उपलब्ध कराया, जिससे किसानों को बिना

किसी परेशानी के खेती की तैयारी करने में सुविधा मिली। सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड के ग्राम कुम्हाररास के किसान सोमारु राम इसकी एक प्रेरणादायक मिसाल हैं। दो एकड़ कृषि भूमि पर खेती करने वाले सोमारु राम को छिंदगढ़ सहकारी समिति के माध्यम से सब्सिडीयुक्त किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण मिला। साथ ही कुकानार समिति से उन्हें समय पर उन्नत धान का बीज तथा एक-एक बोरी यूरिया, डीएपी, एनपीके और पोटाश भी उपलब्ध कराया गया। सोमारु राम बताते हैं कि पहले खेती के मौसम में खाद, बीज और पैसे की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती होती थी। इस बार सभी आवश्यक सामग्री समय पर मिल जाने से उनकी बोआई समय पर शुरू हो गई और आर्थिक चिंता भी दूर हो गई।

किसानों को दिए जा रहे वैज्ञानिक खेती के सुझाव

प्रधानमंत्री आशा योजना के अंतर्गत दलहन-तिलहन को बढ़ावा

■ खरीफ 2026: अल्प एवं अनियमित वर्षा से निपटने कृषि विभाग ने जारी की आकरिष्मक कार्ययोजना

रायपुर/ संवाददाता

खरीफ मौसम 2026 के दौरान संभावित अल्प एवं अनियमित वर्षा की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कृषि विभाग द्वारा आकरिष्मक कार्ययोजना तैयार कर किसानों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उप संचालक कृषि ने बताया कि कम वर्षा की स्थिति में किसानों को संरक्षण जुताई अपनाने की सलाह दी जा रही है। इस तकनीक से मिट्टी की संरचना एवं नमी संरक्षित रहती है, कार्बनिक पदार्थों का संरक्षण होता है तथा भूमि की

जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि किसानों को अपनी भूमि की प्रकृति एवं वर्षा की स्थिति के अनुरूप फसलों का चयन करने, सूखा प्रतिरोधी एवं कम अवधि में पकने वाली उन्नत किस्मों का उपयोग करने तथा डायरेक्ट सीडिंग राइस (डीएसआर) पद्धति अपनाने की सलाह दी जा रही है। डीएसआर तकनीक से धान की रोपाई की आवश्यकता नहीं होती तथा 30 से 40 प्रतिशत तक पानी की बचत संभव है। कृषि विभाग ने हल्की भूमि में तिल, रामतिल एवं मूंगफली तथा भारी भूमि में शीघ्र एवं मध्यम अवधि की धान की किस्मों के साथ ऊपरी भूमि में मूंग, उड़द एवं अरहर की जल्द पकने वाली किस्मों की खेती करने की सलाह दी है। इसके साथ ही कतार पद्धति से बुवाई, मिश्रित खेती तथा बुवाई के समय गोबर खाद अथवा जैविक खाद के उपयोग पर भी विशेष जोर दिया गया है, जिससे कम वर्षा की स्थिति



में भी फसलों का बेहतर विकास हो सके। उप संचालक कृषि ने बताया कि कम वर्षा की स्थिति में किसानों को कम अवधि एवं कम पानी में तैयार होने वाली वैकल्पिक फसलों को अपनाने की सलाह दी जा रही है। इनमें बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग (के-851), पूसा विशाल,

बी.एम.-4, एच.यू.एम.-12, विराट, उड़द (टी-9, पंत यू-30, बरखा, गौतम, टी.यू.-94-2), उड़द, अरहर, तिल, मूंगफली, तोरिया तथा रागी, कोदो एवं कुटकी जैसे मिलेट शामिल हैं। ये फसले अल्पवर्षिक सूखा सहन कर सकती हैं और कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती हैं। इन

फसलों को पारंपरिक फसलों की तुलना में बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। ये फसलें कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती हैं तथा 60 से 80 दिनों में तैयार हो जाती हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आशा योजना के अंतर्गत दलहन एवं तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने से किसानों को उचित मूल्य भी प्राप्त होगा। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने नालों पर अस्थायी कच्चे बांध निर्माण, खेतों में आवश्यकतानुसार सिंचाई, टपक एवं सिंक्रलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के उपयोग, हाथ से निराई, खेत तालाब निर्माण, ढलान के आड़े जुताई, मल्लिचंग तकनीक, कंटूर ट्रैच, एलबीसीडी, गैबियन संरचनाओं तथा डबरी एवं स्टॉप डेम निर्माण जैसे उपाय अपनाने की सलाह दी है। इन उपायों से वर्षा जल का संरक्षण, भू-जल स्तर में वृद्धि, मृदा कटाव को रोकथाम तथा संकेत की स्थिति में जीवनरक्षक सिंचाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

## संपादकीय

अमेरिका स्थित स्वतंत्र प्रबुद्ध संस्था 'द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच' के एक नए वैश्विक सर्वेक्षण के मुताबिक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया के प्रमुख 33 देशों में भारत 24वें स्थान पर है। देश का संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से मौखिक, लिखित, कलात्मक और डिजिटल माध्यमों से अपने विचार व्यक्त कर सकता है। यह

लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है और किसी भी देश के चहुँमुखी विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मगर सवाल है कि क्या सरकार की नीतियों या फैसलों का विरोध करना अपराध की श्रेणी में आता है? इस पर अदालतों की ओर से समय-समय पर स्थिति स्पष्ट की जाती रही है और इसी क्रम में अब वांबे हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि देश के नागरिकों को सरकार का जुल्म नहीं बनाया जा सकता।

## क्या सरकार से असहमति अपराध है? हाई कोर्ट की टिप्पणी ने लोकतंत्र पर छेड़ी नई बहस

किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए जिलाबंद करने का आदेश नहीं दिया जा सकता कि वह सरकार के खिलाफ आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों में शामिल है। ऐसा करना निश्चित रूप से उसके मौलिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार को प्रभावित करता है। सहमति और असहमति दो ऐसे पहलू हैं, जिनकी लोकतंत्र को मजबूती देने में अहम भूमिका है।

संवैधानिक अधिकारों के लिहाज से देखा जाए, तो अगर कोई व्यक्ति शासन-प्रशासन की नीतियों, व्यवस्था या किसी विचारधारा का विरोध करता है, तो उसे स्वस्थ आलोचना के तौर पर देखा जाना चाहिए। मगर देश में ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, जब इस तरह की आलोचना को साजिश या बगवत बता दिया जाता है। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण है कि अगर हर आलोचना या असहमति को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, तो लोकतंत्र का मूल तत्त्व कैसे

जीवित रह पाएगा? वांबे हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में यह सवाल उठाया है कि आम नागरिक सरकार की किसी कार्रवाई या फैसले के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते? क्या यह नागरिकों को सरकार का जुल्म बनाने जैसा नहीं है? इसमें दोराय नहीं कि अगर अन्याय के खिलाफ और सुधार की मांग के पक्ष में उठने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश की जाए, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात नहीं, तो

और क्या होगा। अमेरिका स्थित स्वतंत्र प्रबुद्ध संस्था 'द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच' के एक नए वैश्विक सर्वेक्षण के मुताबिक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया के प्रमुख 33 देशों में भारत 24वें स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि अभिव्यक्ति की आजादी के लिए सैद्धांतिक समर्थन मजबूत बना हुआ है, लेकिन इस अधिकार की रक्षा करने की प्रतिबद्धता दुनिया के कई हिस्सों में कमजोर हो रही है।

## भारत और म्यांमार के बीच संबंधों को नई रणनीतिक धार वाली उच्चस्तरीय वार्ता, चीन को झटका

भारत और म्यांमार के बीच संबंधों को नई रणनीतिक धार देने वाली उच्चस्तरीय वार्ता ने दक्षिण पूर्व एशिया की बदलती भू राजनीतिक तस्वीर में बड़ा संदेश दिया है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्याइंग ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनकर साफ संकेत दिया कि वह चीन की बढ़ती पकड़ से संतुलन बनाने के लिए नई दिल्ली के साथ संबंधों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि ह्याइंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट आश्वासन दिया कि म्यांमार की धरती का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा।

(निरज कुमार दुबे)

देखा जाये तो इस पूरी वार्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू चीन के बढ़ते प्रभाव की पृष्ठभूमि भी है। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन लगातार आर्थिक और सामरिक विस्तार कर रहा है। म्यांमार में भी चीन की बढ़ी निवेश परियोजनाएं और बंदरगाह विकास योजनाएं चल रही हैं।

भारत और म्यांमार के बीच संबंधों को नई रणनीतिक धार देने वाली उच्चस्तरीय वार्ता ने दक्षिण पूर्व एशिया की बदलती भू राजनीतिक तस्वीर में बड़ा संदेश दिया है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्याइंग ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनकर साफ संकेत दिया कि वह चीन की बढ़ती पकड़ से संतुलन बनाने के लिए नई दिल्ली के साथ संबंधों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि ह्याइंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट आश्वासन दिया कि म्यांमार की धरती का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। यह संदेश केवल चीन के लिए ही नहीं बल्कि म्यांमार में सक्रिय उन सशस्त्र गुटों के लिए भी था जो लंबे समय से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति फैलाने की कोशिश करते रहे हैं। इस वार्ता के जरिए भारत ने म्यांमार में चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देते हुए यह दिखा दिया कि क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और सामरिक साझेदारी के मामले में नई दिल्ली अब अधिक आक्रामक और निर्णायक भूमिका निभा रही है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने वार्ता के बाद बताया कि दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों को लेकर सहयोग पर गंभीर चर्चा हुई। यह क्षेत्र आज वैश्विक राजनीति और आर्थिक प्रतिस्पर्धा का अहम हिस्सा बन चुका है क्योंकि आधुनिक प्रौद्योगिकी, रक्षा उपकरण, ऊर्जा परिवर्तन और अर्धचालक उद्योग में इन खनिजों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत लंबे समय से इन संसाधनों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रयासरत है। ऐसे में म्यांमार के साथ सहयोग भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। म्यांमार दुर्लभ मृदा संसाधनों से समृद्ध देश है और भारत इस क्षेत्र में साझेदारी के माध्यम से अपनी आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुरक्षित और विविध बनाना चाहता है।

दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा, क्षमता निर्माण और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत म्यांमार का विश्वसनीय पड़ोसी, भरोसेमंद सहयोगी और संकट के समय सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाला देश बना रहेगा। यह

दृष्टिकोण भारत की 'पड़ोसी प्रथम', 'एकट ईस्ट' और 'महासागर' नीति के अनुरूप है।

वार्ता में सुरक्षा सहयोग सबसे महत्वपूर्ण विषयों में शामिल रहा। म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत को आश्वासन दिया कि उनकी भूमि का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। यह आश्वासन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच लगातार सोलह सौ चालीस किलोमीटर लंबी सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे संवेदनशील पूर्वोत्तर राज्यों से

रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि पूर्वोत्तर भारत का रणनीतिक महत्व भी बढ़ेगा। यह परियोजना भारत की 'एकट ईस्ट' नीति का प्रमुख आधार मानी जाती है।

देखा जाये तो इस पूरी वार्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू चीन के बढ़ते प्रभाव की पृष्ठभूमि भी है। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन लगातार आर्थिक और सामरिक विस्तार कर रहा है। म्यांमार में भी चीन की बढ़ी निवेश परियोजनाएं और बंदरगाह विकास योजनाएं चल रही हैं। ऐसे

महत्वपूर्ण मुलाकात की। इन बैठकों में सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी गुटों की गतिविधियां, अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी, समुद्री सुरक्षा तथा क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत ने साफ किया कि म्यांमार की स्थिरता और वहां शांति बहाली भारत की सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है। अजित डोभाल के साथ हुई बातचीत में सामरिक सहयोग, खुफिया समन्वय और सीमा पर आतंकी नेटवर्क पर निगरानी मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक में व्यापार, संपर्क परियोजनाओं, ऊर्जा सहयोग और पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाली योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।

देखा जाये तो म्यांमार के राष्ट्रपति की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब पूरा क्षेत्र भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति श्रृंखला संकट और सुरक्षा चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। इस यात्रा ने स्पष्ट किया है कि भारत और म्यांमार अपने संबंधों को केवल पारंपरिक पड़ोसी संबंधों तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि उन्हें व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलना चाहते हैं। दुर्लभ खनिजों से लेकर सीमा सुरक्षा और संपर्क परियोजनाओं तक, दोनों देशों की बढ़ती निकटता आने वाले समय में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

कुल मिलाकर म्यांमार के साथ यह पूरी कूटनीतिक पहलू मोदी सरकार की सक्रिय और दूरदर्शी विदेश नीति का मजबूत उदाहरण बनकर सामने आई है। ऐसे समय में जब चीन दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है, भारत ने म्यांमार के साथ सामरिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को नई मजबूती देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में माहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने एक ओर जहां अपने पूर्वोत्तर की सुरक्षा चिंताओं को मजबूती से उठाया, वहीं दूसरी ओर संपर्क परियोजनाओं, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी के जरिए म्यांमार को भरोसेमंद सहयोग का संदेश भी दिया। यह कूटनीतिक सफलता केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भारत की 'एकट ईस्ट' नीति, क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति और एशिया में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच उसकी मजबूत होती भूमिका भी साफ दिखाई देती है। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)



जुड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि हाल के वर्षों में म्यांमार के भीतर अस्थिरता, सशस्त्र समूहों की गतिविधियां, अवैध तस्करी और सीमा पार घुसपैठ भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती रही हैं। विशेष रूप से मणिपुर में जातीय तनाव और हिंसा के बाद सीमा प्रबंधन का महत्व और बढ़ गया है।

भारत और म्यांमार के बीच रक्षा सहयोग का केंद्र प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और संस्थागत विकास रहा है। विदेश सचिव ने कहा कि म्यांमार के सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों से जुड़े प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। साथ ही दोनों देशों ने संपर्क परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। विशेष रूप से कलादान बहु माध्यम पारगमन परिवहन परियोजना को रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार के

में भारत म्यांमार के साथ संबंधों को मजबूत कर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना चाहता है। भारत के लिए म्यांमार केवल पड़ोसी देश नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला सामरिक द्वार है। इसलिए नई दिल्ली इस संबंध को आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा तौरों पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार में शांति, स्थिरता और समावेशी संवाद के समर्थन की भी बात कही। भारत ने संघीय शासन व्यवस्था और आर्थिक विकास के अपने अनुभव साझा करने की पेशकश की। यह संकेत देता है कि भारत म्यांमार में स्थिर राजनीतिक व्यवस्था और दीर्घकालिक शांति को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक मानता है। हम आपको यह भी बता दें कि म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्याइंग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी

उदाहरण बनकर सामने आई है। ऐसे समय में जब चीन दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है, भारत ने म्यांमार के साथ सामरिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को नई मजबूती देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में माहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने एक ओर जहां अपने पूर्वोत्तर की सुरक्षा चिंताओं को मजबूती से उठाया, वहीं दूसरी ओर संपर्क परियोजनाओं, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी के जरिए म्यांमार को भरोसेमंद सहयोग का संदेश भी दिया। यह कूटनीतिक सफलता केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भारत की 'एकट ईस्ट' नीति, क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति और एशिया में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच उसकी मजबूत होती भूमिका भी साफ दिखाई देती है। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

## आधुनिकता के नाम पर चीनी चक्रव्यूह का कसता शिकंजा

(डा. रवीन्द्र अरजरिया)

जैविक हथियारों के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक चक्रव्यूह के जाल में दुनिया को फंसाने की कवायद तेज होती जा रही है। इजरायल ने इसकी शुरुआत सन् 2010 में ईरान के नताज्ज स्थित परमाणु संयंत्रों को एक शक्तिशाली कम्प्यूटर वायरस के द्वारा भौतिक और तकनीकी क्षति पहुंचा कर प्रत्यक्ष रूप में की थी। उसके बाद यह क्रम चल निकला। वायरस बनाने से लेकर उनके व्यापक प्रयोग तक के अनुसंधान में दुनिया के तकनीक सम्पन्न देश जुट गये। सन् 2024 के सितम्बर माह की 17 तारीख को लेबनान स्थित आतंकवादी संगठन हिज्बुल्लाह सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर्स पर इजाराइल ने पूर्व निर्धारित षडयंत्र के तहत साइबर इलेक्ट्रॉनिक अटैक किया। पेजर्स में विस्फोट होते चले गये। आहत होते लोगों की संख्या में इजाफा होता चला गया। अगले दिन 18 सितम्बर को आतंकवादियों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले वॉकी-टॉकी में विस्फोटों का सिलसिला शुरू हुआ। इन विस्फोटों के पीछे की तकनीक ने दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया। इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर एक खास कोडिंग में संदेश भेजा गया था जिससे बैटरी ओवरहीट हुई और अंदर लगा विस्फोटक फट गया। घटना को इजाराइल के तकनीकी अनुसंधान और मोसाद की पकड़ ने दूर से ही अंजाम तक पहुंचाया। वर्तमान में इसी तरह की बानगी देश में देखने को मिल रही है। राजधानी सहित अनेक हिस्सों में ई-

रिक्शा की लिथियम बैटरी को रिमोटली हक किये जाने की घटनायें सामने आ रही हैं। बीएटी-बीएमएस तथा इंपोच ली इओन जैसे चाइनीज मोबाइल ऐप्स के माध्यम से शरातती तत्वों ने ई-रिक्शों को निशाना बनाया। ई-रिक्शों में उपयोग होने वाली आधुनिक लिथियम बैटरी निर्माताओं ने उनमें ब्लूटूथ-बेस्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस लगा दिया जिसे ब्लूटूथ के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। बैटरियों की आपूर्ति करने वाली कम्पनियों ने तकनीक डिजाइन में ब्लूटूथ षडयंत्र सहित अनेक नकारात्मक साइबर प्रक्रियायें जोड़ी गई हैं ताकि आवश्यकतानुसार उनका उपयोग निहित इच्छित लक्ष्य भेदन हेतु किया जा सके। फिलहाल इस तकनीक के माध्यम से शरातती तत्व दूर से ही वाहनों को लॉक कर रहे हैं। साइबर हैकिंग और चालकों को हो रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने बैटरी हक करने वाले इन सॉफ्टवेयर को गूगल प्ले स्टोर और एपल एप स्टोर से हटाने के आदेश दे दिये हैं। यह महज तत्काल मिलने वाली राहत है। इस बानगी ने आने वाले समय की विकराल विभीषिका का स्पष्ट संकेत दे दिया है। इन बैटरियों को जब शरातती तत्वों द्वारा केवल मोबाइल के एप से ब्लूटूथ को माध्यम बनाकर नियंत्रित किया जा सकता है तो फिर बैटरियों के निर्माताओं द्वारा विकसित की गई इस तकनीक के अन्य फीचर बैटरियों में ब्लास्ट जैसी घटनायें भी आसानी से कर सकते हैं। यह मामला केवल ई-रिक्शा तक

वायरस बनाने से लेकर उनके व्यापक प्रयोग तक के अनुसंधान में दुनिया के तकनीक सम्पन्न देश जुट गये। सन् 2024 के सितम्बर माह की 17 तारीख को लेबनान स्थित आतंकवादी संगठन हिज्बुल्लाह सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर्स पर इजाराइल ने पूर्व निर्धारित षडयंत्र के तहत साइबर इलेक्ट्रॉनिक अटैक किया। पेजर्स में विस्फोट होते चले गये। आहत होते लोगों की संख्या में इजाफा होता चला गया। अगले दिन 18 सितम्बर को आतंकवादियों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले वॉकी-टॉकी में विस्फोटों का सिलसिला शुरू हुआ। इन विस्फोटों के पीछे की तकनीक ने दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया। इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर एक खास कोडिंग में संदेश भेजा गया था जिससे बैटरी ओवरहीट हुई और अंदर लगा विस्फोटक फट गया।

ही सीमित नहीं है। कार, स्कूटी, बस, ट्रेन, हेलीकाप्टर, हवाई जहाज सहित अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी इसी तरह की बैटरियों का धड़ले से उपयोग किया जा रहा है। अत्याधुनिक बैटरियों का नाम पर सुविधाओं

प्रतीत होती है जो पूरी तरह सफल हुईं। इतिहास गवाह है कि चीन ने ही अपनी प्रयोगशाला में तैयार किये गये कोरोना वायरस के द्वारा संसार को कभी न भूलने वाला जखम दिया था। प्रमाण मिलने के बाद भी विश्व स्वास्थ्य



का अम्बार दिखाने वाली अनेक कम्पनियों अपने पूर्व निर्धारित षडयंत्र के तहत आमजन तक घातक पहुंच बनाने में जुटी हैं। बैटरियों को ओवर हीट करके विस्फोट करने वाली तकनीक तो प्रयोग के तौर पर आजमाई गई

संगठन जैसी संस्थायें भी चीन के इस घातक षडयंत्र पर खामोश ही रहीं। चीन की वर्तमान घातक तकनीक के आगे समूचा संसार नतमस्तक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी अपने चीन दौर के दौरान इलेक्ट्रॉनिक

उपकरणों के उपयोग में बेहद सावधानी बरती थी। समूचा संसार चीन के सस्ते इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रति पागलपन की हद तक दीवाना हो चुका है। इन उपकरणों को बेहद जटिल और सूक्ष्म तकनीक के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। सुपर नैनो टैक्निक को आधार बनाकर चीन निरंतर नवीन अविष्कार करने में जुटा है। जासूसी उपग्रह, ठोड़ी विमान, घातक वायरस, डाटा चोरी तकनीक, हैकिंग सिस्टम जैसे अगिनत घातक कारकों के माध्यम से चीन का नकारात्मक सिंहासन निरंतर मजबूत होता जा रहा है। समूची दुनिया में कट्टरपंथियों की मौजूदगी की तरह ही चाइनीज उपकरणों की भरमार है। छोटे बच्चों से लेकर उम्रदायज लोगों तक, छात्रों से लेकर शोधकर्ताओं तक और सरकारी तंत्र से लेकर निजी संस्थाओं तक में चीन के उत्पादों का धड़ले से उपयोग हो रहा है। इन उपकरणों का आयात से पहले जांचें, परखने और दूरगामी परिणामों की समीक्षा करने वाले उतरदायी विभाग के कर्तव्यों को लापरवाही, मनमानी या उपेक्षा की श्रेणी तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता बल्कि यह मीराजफरोज जमातों के द्वारा

संपन्न किये जाने वाला एक राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी और मानवता विरोधी कार्य है जिसके लिए दण्ड का सर्वोच्च विधान होना नितान्त आवश्यक है। जमीन की गलत नाप, गलत प्रविष्टि और गलत निर्णय देने वाले किसी भी सरकारी अधिकारी को कभी दण्डित नहीं किया जाता बल्कि पीड़ित को स्वयं दोषी अधिकारी के कृत्य को ठीक कराने हेतु लम्बी सजा भुगतना पड़ती है। देश की बिगड़ चुकी आन्तरिक व्यवस्था के लिए अल्पकालिक सरकारें ही नहीं बल्कि चिरस्थायी लोकसेवकों की मनमानियां ही उतरदायी हैं जिनमें सत्ता लोचुपों का पूरा सहयोग रहता है। वर्तमान में देश के बिगड़ते जा रहे हालातों के साथ-साथ सांसारिक अशांति के लिए सुख की नींद में रहने वाले विलासियों की निजी संचय की प्रवृत्ति ही उतरदायी है। यहां यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि चीन के साइबर इलेक्ट्रॉनिक चक्रव्यूह में समूचा संसार फंस चुका है। घर-घर, दफ्तर-दफ्तर और जगह-जगह चीना गैजेट्स विक्रेते पड़े हैं। कभी भी, किसी भी उपकरण को दूर से ही विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

# 27 प्रतिशत आरक्षण और जनगणना में अलग कॉलम के लिए 19 अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन का शंखनाद

भानुप्रतापपुर। छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज द्वारा भानुप्रतापपुर में एक महत्वपूर्ण संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले लगभग 20 अलग-अलग समाजों के जिला अध्यक्ष और प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से ओबीसी समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण देने और जनगणना में ओबीसी के लिए अलग से कॉलम बहाल करने की मांग को लेकर रणनीति तैयार की गई। अपनी मांगों को मनवाने के लिए समाज ने चरणबद्ध तरीके से बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। बैठक में निर्णय लिया गया कि आंदोलन के पहले चरण में 19 अगस्त को कांकेर जिला मुख्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद बस्तर संभाग के सभी जिलों में सिलसिलेवार तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। जिला स्तर के बाद इस आंदोलन को संभाग स्तरीय और अंत में प्रदेश स्तरीय रूप दिया जाएगा। पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा हमारी मुख्य मांग 27 प्रतिशत आरक्षण है। हमें अपना ध्यान इधर-उधर भटकाए बिना संगठन को और मजबूत बनाना है और बस्तर संभाग के हर जिले में एकजुट होकर आवाज उठानी है।



**एकजुटता पर जोर: नेतृत्वकर्ता समाज को दिशा देता है : टिकेश्वरी जैन**

बैठक को संबोधित करते हुए टिकेश्वरी जैन ने कहा कि 27 प्रतिशत आरक्षण को लक्ष्य के लिए हो 'सर्व ओबीसी समाज' का गठन किया गया है। उन्होंने समाज में एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा, नेतृत्वकर्ता ही समाज को सही दिशा और दशा देता है। आज हमें आपसी मतभेद भुलाकर एक होकर लड़ना है। जो सच में समाज के लिए लड़ता है, उसे किसी पद की जरूरत नहीं होती। जो केवल पद के भूखे हैं, वे समाज का विकास नहीं कर सकते। उन्होंने समाज को तोड़ने की कोशिश करने

## वले तत्वों से सावधान रहने की अपील की। जनगणना से ओबीसी कॉलम हटाना चिंताजनक: हरेश चक्रधारी

पदाधिकारी हरेश चक्रधारी ने समाज की दो प्रमुख मांगों को रेखांकित करते हुए कहा कि एक तरफ 27 प्रतिशत आरक्षण हमारी जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ 10 वर्षों में होने वाली जनगणना से ओबीसी का कॉलम (वर्ग) ही हटा दिया गया है। इसके कारण समाज को राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं (चुनावों) में उचित हिस्सेदारी मिलने में बाधा आ रही है। इसके खिलाफ पहले चरण में बस्तर संभाग के सभी

## जिलों में शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय संगठन भंग, नई कोर कमेटी संभालेगी कमान

बैठक के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में महत्वपूर्ण संगठनात्मक फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का नया पंजीयन कराया गया। इसके साथ ही, पुराने प्रदेश अध्यक्ष व सभी पदाधिकारियों व प्रदेश स्तरीय संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग करने की घोषणा की गई। नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा अपने निजी लाभ के लिए संगठन के लेटरपैड का दुरुपयोग किया जा रहा था। समाज के

हितों को सर्वोपरि रखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है। अब आगे की पूरी कमान और आंदोलन का संचालन एक विशेष कोर कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। नेताओं ने याद दिलाया कि प्रदेश में ओबीसी समाज की जनसंख्या लगभग 40 से 50 प्रतिशत है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

## बैठक में ये रहे प्रमुख रूप से उपस्थित

इस संभाग स्तरीय बैठक और प्रेसवार्ता के दौरान डड़सेना कलार समाज के संभाग महामंत्री सोनी लाल जैन, बंजारा समाज के जिलाध्यक्ष सुभिया चौहान, संतोष साहू, फूलचंद दिवान, मनीष नाथ योगी, भगवती गर्जेद, अनिता सोनी, अरविन्द जैन, हरेश चक्रधारी, ज्वाला प्रसाद जैन, राजिव श्रीवास, भारत निषाद, जितेंद्र जयसवाल, कमलेश निषाद, चंद्रशेखर यदु, हरी यादव, लक्ष्मी यादव, भुनेश सेन, विनोद पटेल, गजानंद जैन, मुकेश चंद्रकर, सुरेश जैन, दीनदयाल पटेल, रवि साहू, धनसिंह विश्वकर्मा सहित सर्व ओबीसी समाज के विभिन्न घटकों के पदाधिकारी एवं भारी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

## प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में पंचवर्षीय तथा वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

कांकेर। जिला खनिज संस्थान न्यास निधि प्रबंधकारिणी समिति की बैठक कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसके तहत स्वीकृत निर्माणाधीन कार्यों तथा अपूर्ण कार्यों की समीक्षा की गई। इसके अलावा पंचवर्षीय एवं वार्षिक निर्माण कार्यों की कार्ययोजना तैयार किए जाने के संबंध में विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि जो कार्य लंबित हैं तथा अब तक प्रारंभ नहीं हो पाए हैं, उन्हें निरस्त कर राशि वापस जमा कराए। कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में कलेक्टर ने विभागवार स्वीकृत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने ऐसे स्वीकृत कार्य जो अब तक प्रारंभ नहीं हो पाए हैं, पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें निरस्त करने तथा आर्बिट्रेट राशि वापस जमा कराने के लिए जिला पंचायत के सीईओ हरेश मंडवी को निर्देशित किया। कलेक्टर ने डीएमएफ मद से जिले में स्वीकृत निर्माण एवं विकास कार्यों की वर्षवार एवं विभागवार आर्बिट्रेट राशि के व्यय और निर्माण कार्य की स्थिति की जानकारी ली। इसके अलावा बैठक में पंचवर्षीय एवं वार्षिक निर्माण कार्यों के विभाग द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना एवं प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

## बोधघाट थाना बना छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना



जगदलपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस और बस्तर पुलिस के लिए गर्व का क्षण है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 को वार्षिक पुलिस थाना 27 प्रतिशत में बस्तर जिले के बोधघाट थाना को छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। यह उपलब्धि इसलिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि पहली बार बस्तर संभाग के किसी थाना को यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस थानों का मूल्यांकन अपराध नियंत्रण, अनुसंधान की गुणवत्ता, सामुदायिक पुलिसिंग, जनसहभागिता, नागरिक-अनुकूल कार्यप्रणाली, पुलिस अधीनस्थ, नवाचार, अभियंता संघर्षण तथा समग्र कार्य निष्पादन जैसे

विभिन्न मानकों के आधार पर किया जाता है। इन सभी मापदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते बोधघाट थाना को यह सम्मान मिला। सम्मान समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री के नाम से जारी प्रशस्ति-पत्र तत्कालीन बस्तर पुलिस महानिरीक्षक पी. सुंदरराज तथा वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक बदीनारायण मोना द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक लीलाधर राउटे एवं वर्तमान थाना प्रभारी निरीक्षक तामेश्वर चौहान को प्रदान किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाथ, तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीशमल तथा वर्तमान नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार घोड़े भी

मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने इसे बोधघाट थाना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वर्षों की मेहनत, अनुशासन और जनसेवा के प्रति समर्पण का परिणाम बताया। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में थाना द्वारा अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था, सामुदायिक पुलिसिंग, जनविश्वास बढ़ाने और नवाचार आधारित पुलिसिंग के क्षेत्र में किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। बस्तर पुलिस ने इस सम्मान को पूरे पुलिस बल के सामूहिक प्रयास और उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का प्रतीक बताया है। यह उपलब्धि भविष्य में भी नागरिक-केंद्रित और जवाबदेह पुलिसिंग के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

# कम वर्षा से निपटने कृषि विभाग की आकस्मिक कार्ययोजना जारी, किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने की सलाह

डीएसआर तकनीक, सूखा सहनशील फसलें और जल संरक्षण उपायों पर जोर, प्रधानमंत्री आशा योजना से दलहन-तिलहन उत्पादकों को मिलेगा लाभ

जगदलपुर। खरीफ मौसम 2026 में संभावित अल्प एवं अनियमित वर्षा को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए आकस्मिक कार्ययोजना जारी की है। कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पत्रा के मार्गदर्शन में तैयार इस योजना के तहत किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने, कम पानी में तैयार होने वाली फसलों का चयन करने तथा जल संरक्षण के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। उप संचालक कृषि श्री के.एन. मरकाम ने बताया कि कम वर्षा की स्थिति में संरक्षण जुताई, डायरेक्ट सीडिंग राइस (डीएसआर) तकनीक और सूखा प्रतिरोधी एवं कम अर्वाधि में पकने वाली उन्नत किस्मों का उपयोग किसानों के



लिए लाभदायक रहेगा। डीएसआर पद्धति से धान की रोपाई की आवश्यकता नहीं होती और 30 से 40 प्रतिशत तक पानी की बचत संभव है। कृषि विभाग ने हल्की भूमि में तिल, रामतिल और मूंगफली तथा भारी भूमि में शीघ्र

एवं मध्यम अर्वाधि की धान की किस्मों को खेती की सलाह दी है। वहीं ऊपरी भूमि में मूंग, उड़द और अरहर जैसी दलहनी फसलों की जल्द पकने वाली किस्मों को अपनाने पर जोर दिया गया है। कतार पद्धति से बुवाई, मिश्रित

खेती और गोबर खाद या जैविक खाद के उपयोग की भी सलाह दी गई है। विभाग ने बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द, अरहर, तिल, मूंगफली, तोरिया तथा रागी, कोदो और कुटकी जैसे मिलेट्स को वैकल्पिक फसलों के रूप में अपनाने की अपील की है।

ये फसलें कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती हैं और 60 से 80 दिनों में तैयार हो जाती हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आशा योजना के तहत दलहन एवं तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी होने से किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना रहेगी। जल संरक्षण के लिए खेत तालाब, अस्थायी कच्चे बांध, टपक एवं स्प्रींकलर सिंचाई, मल्लिचंग, कटर ट्रेंच, गेबियन संरचना, डबरी और स्टॉप डैम जैसे उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग ने किसानों से मौसम के अनुरूप वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कर फसल उत्पादन और आय पर कम वर्षा के प्रभाव को न्यूनतम करने की अपील की है।

## मोदकपाल हाट बाजार में पुलिस ने दी साइबर ठगी और नशे से बचने की सीख

### 'मावा पुलिस केतुल' अभियान के तहत नुकड़ नाटक से भी किया जागरूक

बीजापुर। मोदकपाल के साप्ताहिक बाजार में बुधवार को पुलिस ने 'मावा पुलिस केतुल' अभियान के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को यातायात नियमों, साइबर अपराध, नशासुराई और सामुदायिक पुलिसिंग के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और युवा शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान रोड सेफ्टी सेल के अध्यक्ष सिन्हा ने सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण बताते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर कई दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। यातायात नोडल अधिकारी एवं उप पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार साहू ने बड़े साइबर अपराधों को लेकर ग्रामीणों को सतर्क किया।



उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी, एटीएम या यूपीआई पिन किसी के साथ साझा न करें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल 1930 हेल्पलाइन या नजदीकी थाने में सूचना देने की अपील की। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर सकारात्मक जीवन अपनाने का

भी आह्वान किया। थाना प्रभारी आकाश मसीह ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास अपराध नियंत्रण की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने ग्रामीणों से अवैध गतिविधियों, नशे के कारोबार और संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी बिना संकोच पुलिस तक पहुंचाने की अपील की। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण डीआरजी जवानों की ओर से

प्रस्तुत नुकड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुति रही। इसके माध्यम से नशासुराई, साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों का संदेश सरल और रोचक ढंग से ग्रामीणों तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम में सरपंच कमला भगत, उपसरपंच सदाशिव अलसा, पंच जव्वा शंकर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।



## डीएचपीब्लिक स्कूल किरंदुल के स्काउट्स एवं गाइड्स इकाई ने दिया हरियाली का संदेश, और किया वृहत वृक्षारोपण

किरंदुल। वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत डीएचपीब्लिक स्कूल किरंदुल में विद्यालय के प्राचार्य एस के श्रीवास्तव के नेतृत्व में स्काउट एवं गाइड इकाई द्वारा बुधवार सुबह 11 बजे विद्यालय परिसर में फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर रेंजर लीडर तुषि श्रीवास्तव, गाइड कैप्टन अनामिका एका, स्काउट मास्टर नारायण प्रसाद, कब मास्टर राकेश कुमार, गाइड कैप्टन सुरभी राव तथा विद्यालय के स्काउट्स-गाइड्स एवं रोवर-रेंजर छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में पपीता, अमरूद, आंवला, सहजन एवं नींबू के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया। सभी प्रतिभागियों ने हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण हेतु पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया।

# सलिहाघाट जांजगीर चांपा ब्रिज खस्ताहाल, जगह जगह बने गड्डे, नजर आ रही सरिया, वाहन चालकों के लिए बना खतरा

## मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति करने से बिगड़ी स्थिति, भटगांव, बिरा चांपा और कोरबा पहुंचने का मुख्य मार्ग

भटगांव। नगर भटगांव से 8 किलोमीटर दूर सलिहाघाट महानदी पर बना पुल पुरी तरह से जर्जर हो चुका है। यह पुल जांजगीर चांपा जिला और कोरबा जिला को जोड़ता है। वहीं इस पुल की मरम्मत नहीं होने के कारण इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गयी है। इतना ही नहीं इस महानदी पुल में जगह-जगह गड्डे हो गये हैं और लोहे के सरिया बाहर निकल आए हैं। इस मार्ग से गुजरने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डाल कर यात्रा करने को मजबूर हो गये हैं। आपको बता दें कि लोगों की दूरी कम हो इसके लिए महानदी सलिहाघाट में पुल का निर्माण करवाया गया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों को पुल की स्थिति की जानकारी होने के बावजूद अब तक न तो इस पुल की मरम्मत कराई गई और न ही इसके लिए कोई बजट में मांग की गई है। लोग जो हैं लोहे के सरिए से बचते हुए अपनी गाड़ी चलाने को मजबूर हैं। इस पुलिसिया की निर्माण ब्रिज सेतु योजना



के तहत इस पुल का निर्माण कराया गया था। यह मार्ग भटगांव से चांपा, जांजगीर और कोरबा जाने के लिए सबसे कम दूरी और सुगम रास्ता है। इतना ही नहीं स्थानीय लोगों के द्वारा की वर्षों तक इस पुल निर्माण की मांग की गई थी, जिसके बाद इसका निर्माण हुआ लेकिन निर्माण होने के बाद से ना तो इसकी मरम्मत की गई और ना ही पेचवर्क

किया गया। पुल में बने गड्डे और निकले सरिए बड़ी दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने इस सलिहाघाट पुल की मरम्मत की मांग की है। वहीं यह ब्रिज भटगांव, बिरा, चांपा और कोरबा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। इस पुल से लाखों वाहन और राहगीर इस मार्ग का उपयोग करते हैं। यह जांजगीर चांपा और कोरबा



जाने का सबसे कम दूरी वाला सीधा मार्ग है। इसी वजह से भारी वाहन, चार पहिया और दो पहिया वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। आसपास के लोगों के लिए चांपा स्टेशन भी नजदीक है। सलिहाघाट पुल इन? दिनों लोगों की जान पर आपत बना हुआ है। मरम्मत के कुछ ही दिनों बाद ही पुल है खड्ड जाता -अपार पुल की

रिपेयरिंग समय समय पर केवल खानापूर्ति के रूप में की गई। मरम्मत के कुछ ही दिनों बाद पुल फिर से खड्ड जाता है और लोगों की समस्या जस की तस बनी रहती है। ऐसे में लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस पुल की मरम्मत की जाए ताकि आवागमन बाधित न हो और बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। जानकारी के अनुसार सलिहाघाट

पुल का निर्माण विलासपुर डिवीजन से किया गया है। देखरेख और मरम्मत का कार्य भी इसी डिवीजन द्वारा किया जाता है। इस मार्ग में ब्रिज सहित लगभग एक किलोमीटर का हिस्सा इतना जर्जर है कि यदि लोग ध्यान न दें तो हादसा होना तय है। करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए पुल की मरम्मत नहीं कराई गई तो यह पूरी तरह से

जर्जर हो जाएगा। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल में लगी रेलिंग और बाहर निकले सरिए मौत को दबत दे रहे हैं। पुल के बड़े बड़े गड्डे भी दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। संबंधित विभाग और ठेकेदार इस स्थिति से बेखबर हैं। प्रशासनिक अनेदेखी का खमियाज आमजन को भुगतना पड़ रहा है। आप दिन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं।

संक्षिप्त समाचार

पेट्रोल पंप पर बाइक टकराने से शुरू हुआ विवाद, आरक्षक समेत दो पर मारपीट का केस

**बिलासपुर।** तारबाहर थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर बाइक टकराने के मामूली विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। घटना में एक युवक ने पुलिस आरक्षक और उसके साथी पर मारपीट का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रजनेश सिंह ने आरक्षक अभिषेक बक्श को लाइन अटैच कर दिया है। पुलिस के अनुसार, दयालबंद निवासी शिवा गोरख ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह मीडिया कर्मी है। मंगलवार रात करीब 8 बजे वह शिव टाकोज चौक से रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित अंबा पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने पहुंचा था। पेट्रोल पंप पर भीड़ होने के कारण उसकी बाइक सतीश ताती की बाइक से टकरा गई, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान सतीश ताती ने अपने परिचित आरक्षक अभिषेक बक्श को मोबाइल पर बुला लिया। मौके पर पहुंचे आरक्षक ने भी शिवा के साथ मारपीट की और सतीश ने भी उसकी पिटाई की। घटना के बाद शिवा गोरख ने तारबाहर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सतीश ताती और आरक्षक अभिषेक बक्श के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने तत्काल प्रभाव से आरक्षक अभिषेक बक्श को लाइन अटैच कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बलासपुर में सुखानाला के पास वृद्ध भालू का शव मिला, रेस्क्यू सिस्टम पर उठे सवाल

**बिलासपुर।** जिले के खोंगसरा-टेंगनामाड़ा मार्ग स्थित सुखानाला में एक वृद्ध भालू का शव मिलने से वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था और रेस्क्यू सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भालू पिछले कई दिनों से भोजन और पानी की तलाश में जंगल से निकलकर आसपास के गांवों और तेंदुपत्ता पहाड़ों के पास भटक रहा था, लेकिन समय रहते उसका रेस्क्यू नहीं किया गया। मंगलवार को सुखानाला क्षेत्र में भालू का शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृत भालू काफी वृद्ध और कमजोर था। हालांकि उसकी मौत किन कारणों से हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। वन विभाग ने शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है। इधर, स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि भालू के लगातार आबादी वाले क्षेत्र में आने की सूचना पर समय रहते कार्रवाई की जाती, तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल वन विभाग का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही की जाएगी।

40 दिन बाद कब्र से निकाला गया डेढ़ वर्षीय मासूम का शव, करंट से मौत मामले में नया मोड़

**गौरला-पेण्डूर-मरवाही।** जिले के गौरला विकासखंड के रानीझांप गांव में डेढ़ वर्षीय मासूम की कथित करंट लगने से हुई मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। घटना के करीब 40 दिन बाद प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में बच्चे के शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। ज्ञानकारी के अनुसार, 30 मई 2026 को सुबह रानीझांप गांव निवासी योगेश कुमार राठीर का डेढ़ वर्षीय पुत्र पार्थ राठीर अपनी मां के साथ आंगनबाड़ी केंद्र गया था। पार्थ की मां वहां सहायिका के पद पर कार्यरत हैं। बताया गया कि सुबह करीब 7 बजे योगेश अपनी पत्नी को आंगनबाड़ी छोड़कर पास में नहाने चले गए। इसी दौरान मासूम खेलते हुए रास्ते में लगे सोलर हैंडपंप के लोहे के स्टींड के संपर्क में आ गया। परिजनों का आरोप है कि स्टींड में करंट प्रवाहित हो रहा था, जिसकी चपेट में आने से बच्चे की मौत पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता योगेश राठीर ने स्थानीय पंचायत और बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सोलर हैंडपंप की मोटर खराब होने के बाद कथित तौर पर बिना स्टार्टर लगाए सोधे सोलर स्टींड से बिजली पंप जोड़ दिया गया था। इसके कारण पानी फैलने से लोहे के स्टींड और आसपास के क्षेत्र में करंट प्रवाहित होने लगा। योगेश का दावा है कि बेटे को बचाने के दौरान उन्हें भी करंट लगा, लेकिन वे बच गए, जबकि मासूम की मौत पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, घटना के समय परिवार बहद सदमे में था। इसी कारण पुलिस को सूचना दिए बिना और पोस्टमार्टम कराए बिना बच्चे का अंतिम संस्कार कर शव को दफना दिया गया था।

खतरे का स्तर बढ़ते ही संबंधित अधिकारियों के मोबाइल पर तत्काल अलर्ट मेसेज

12 महत्वपूर्ण रेलवे पुलों पर स्थापित है आधुनिक वाटर लेवल मॉनीटरिंग सिस्टम

रेलवे पुलों पर जलस्तर की 24x7 रियल-टाइम निगरानी से संरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित

आधुनिक सेंसर आधारित तकनीक से बाढ़ के दौरान निगरानी हुई अधिक प्रभावी एवं विश्वसनीय

**बिलासपुर।** मानसून के दौरान रेलवे पुलों पर नदियों के जलस्तर की सतत एवं सटीक निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में आधुनिक वाटर लेवल मॉनीटरिंग सिस्टम को अपनाया गया है। सेंसर आधारित यह अत्याधुनिक प्रणाली वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 12 महत्वपूर्ण रेलवे पुलों पर स्थापित की गई है। यह प्रणाली 24 घंटे

रियल-टाइम में जलस्तर की निगरानी करते हुए संरक्षित एवं निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पूर्व में नदियों के जलस्तर का आकलन पारंपरिक मीटर गेज प्रणाली के माध्यम से किया जाता था, जिसमें मैनुअल रीडिंग लेने के कारण सूचना प्राप्त होने में विलंब तथा त्रुटि की संभावना बनी रहती थी। अचानक जलस्तर बढ़ने की स्थिति में समय पर जानकारी उपलब्ध न होने से रेलवे ट्रेक एवं पुलों की संरक्षा का त्वरित आकलन करना चुनौतीपूर्ण होता था। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आधुनिक वाटर लेवल मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। यह प्रणाली सेंसर आधारित तकनीक के माध्यम से पुलों पर लगे जलस्तर संकेतकों की निरंतर निगरानी करती है तथा ट्रेक मैनेजमेंट सिस्टम से एकीकृत रहती है। जैसे ही नदी का जलस्तर पूर्व निर्धारित चेतावनी अथवा खतरे के स्तर तक पहुंचता है अथवा उसमें महत्वपूर्ण



परिवर्तन होता है, सिस्टम स्वतः संबंधित अधिकारियों एवं अभियंताओं के मोबाइल फोन पर तत्काल एसएमएस अलर्ट भेज देता है। इससे आवश्यक सुरक्षा उपाय समय रहते लागू किए जा सकते हैं तथा रेल परिचालन को संरक्षित बनाए रखने में सहायता मिलती है। इस प्रणाली में संबंधित सहायक मंडल अभियंता, रेल पथ निरीक्षक (पीडब्ल्यूआई) सहित अन्य

अधिकृत अधिकारियों के मोबाइल नंबर पंजीकृत रहते हैं। परिणामस्वरूप जलस्तर में होने वाले प्रत्येक महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों तक पहुंच जाती है, जिससे त्वरित निर्णय लेने और आवश्यक कार्रवाई करने में सुविधा होती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जिन 12 महत्वपूर्ण रेलवे पुलों पर वाटर लेवल मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है,

वे निम्नानुसार हैं— 1. झारसुगुड़ा-ईब स्टेशनों के मध्य ईब नदी पर रेलवे पुल क्रमांक 184 अप। 2. ईब-ब्रजराजनगर स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 182 अप। 3. भूपदेवपुर-रावटर्सन स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 86 अप। 4. कोरबा-डुमकेवाड़ा रोड स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 63 डाउन। 5. नैला-चांपा स्टेशनों के मध्य हसदेव नदी पर रेलवे पुल क्रमांक 46 डाउन। 6. जयरामनगर-अकलतरा स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 12 मिडिल। 7. दगौरी-निर्पनिया स्टेशनों के मध्य शिवनाथ नदी पर रेलवे पुल क्रमांक 462 मिडिल। 8. रसमड़ा-दुर्ग स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 348 डाउन। 9. मुंडीकोटा-डुमकेवाड़ा स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 116 अप। 10. कन्हान-कामटी स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 34 अप। 11. वडसा-ब्रह्मपुरी स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 159। 12. बरगौरी-गवरीघाट स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 348 डाउन।

कलेक्टर ने ली महिला एवं बाल विकास विभाग की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न...

कुपोषण मुक्ति हेतु कैलेंडर आधारित कार्ययोजना पर विशेष बल

बाल विवाह मुक्त सूरजपुर बनाने प्रचार-प्रसार बढ़ाने के निर्देश

**सूरजपुर संवाददाता।** कलेक्टर श्रीमती रेना जमील की अध्यक्षता में आज कलेक्टर सभा कक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण चक्र से बाहर निकालने तथा जिले में कुपोषण को गणय स्तर तक लाने की दिशा में संबंधित अधिकारियों को कैलेंडर आधारित कार्ययोजना के तहत कार्य



करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विभाग अंतर्गत रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों पर भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। कलेक्टर ने इन रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कार्यशीली में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। बैठक में बाल विवाह के संबंध में गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई। कलेक्टर ने बाल विवाह को समाज के लिए अभिशाप बताते हुए इसके विरुद्ध सामाजिक स्तर पर अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा

कि प्रचार-प्रसार में बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को अधिक से अधिक उजागर किया जाए, ताकि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुदृष्टि पर पूर्ण रूप से रोक लगाकर सूरजपुर जिले को बाल विवाह मुक्त जिला बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए समाज के सामूहिक प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने सीएससी के कम्प्यूटर ऑपरेटर्स से समन्वय स्थापित कर पात्र हितग्राहियों के शत-प्रतिशत आधार कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग तेज, जिला शिक्षा अधिकारी ने किया कोटा के विद्यालयों का निरीक्षण

विद्यार्थियों से किया संवाद, अध्यापन व्यवस्था, शैक्षणिक अभिलेखों और वार्षिक कैलेंडर का लिया जायजा

**बिलासपुर।** जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देश पर विद्यालयों का सघन निरीक्षण अभियान जारी है। कलेक्टर द्वारा प्राचार्यों एवं संकुल शैक्षिक समन्वयकों को बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारी लगातार विद्यालयों का



निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में नवपदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर जायसवाल ने आज कोटा विकासखंड के शासकीय विद्यालय तेंदुआ, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय करगौकला, शासकीय हाई स्कूल धूमा तथा सेजेस विद्यालय कोटा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद

किया तथा उनकी शैक्षणिक प्रगति की जानकारी ली। साथ ही अध्यापन व्यवस्था, वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर, शिक्षकों की दैनंदिनी, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति सहित अन्य आवश्यक अभिलेखों का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यालयों में नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विकसित किया अभिनव 'रेन वाटर इन्ग्रेस टेस्ट बेंच.....'

अब बिना बारिश के भी होगी रेल कोचों में पानी रिसाव की जांच

स्वदेशी नवाचार से यात्रियों को मिलेगा अधिक सुरक्षित एवं आरामदायक सफ़र

**बिलासपुर।** दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कोचिंग डिपो ने नवाचार, संरक्षा एवं यात्री सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए रेल कोचों में वर्षा जल के रिसाव (रेन वाटर इंग्रेस) की जांच के लिए स्वदेशी 'रेन वाटर इन्ग्रेस टेस्ट बेंच' विकसित किया है। इस अभिनव

प्रणाली के माध्यम से कृत्रिम वर्षा (आर्टिफिशियल रेन सिमुलेशन) का वातावरण तैयार कर कोचों की छत, खिड़कियों, साइड पैनलों तथा अन्य संवेदनशील जोड़ों से होने वाले संभावित जल रिसाव की प्रभावी जांच एवं समय रहते उसका निराकरण किया जा सकेगा। अब तक वर्षा जल के रिसाव की पहचान मुख्यतः प्राकृतिक बारिश पर निर्भर रहती थी, जिसके कारण वर्षभर इसकी जांच संभव नहीं हो पाती थी। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर कोचिंग डिपो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए अधिकांशतः स्कूप सामग्री से इस टेस्ट बेंच का डिजाइन एवं निर्माण किया। केवल कुछ आवश्यक पुर्जों की ही बाजार



से खरीद की गई, जिससे यह प्रणाली अत्यंत किफायती एवं संसाधन-समर्थ सिद्ध हुई है। यह अभिनव टेस्ट बेंच वर्षभर कृत्रिम वर्षा परीक्षण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कोचों में छिपे हुए जल रिसाव की समय रहते पहचान कर उसे सेवा में शामिल करने से पहले ही दूर किया जा सकता है। इससे मानसून के दौरान

यात्रियों को जल रिसाव जैसी असुविधाओं से राहत मिलेगी, कोचों की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा बार-बार होने वाले रखरखाव की आवश्यकता भी कम होगी। इसकी पोर्टेबल डिजाइन के कारण इसका उपयोग पारंपरिक कोचों के साथ-साथ आधुनिक वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों के कोचों में भी किया जा सकता है। यह स्वदेशी नवाचार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता, रचनात्मक सोच एवं संसाधनों के प्रभावी उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह पहल न केवल कोच अनुरक्षण की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, बल्कि यात्रियों को अधिक सुरक्षित, आरामदायक एवं बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

एसईसीएल की पाँच खदानों को मिला 5-स्टार दर्जा, उत्कृष्ट खनन का राष्ट्रीय सम्मान



बंगवार, खैराहा, बेहराबांध, विजय वेस्ट एवं जगन्नाथपुर परियोजना को कोयला मंत्रालय की प्रतिष्ठित 5-स्टार रेटिंग

**बिलासपुर।** साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने उत्कृष्ट एवं उच्चदर्जा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोयला मंत्रालय की प्रतिष्ठित स्टार रेटिंग में अपनी पाँच खदानों को 5-स्टार रेटिंग प्राप्त की है। बंगवार भूमिगत खदान (सोहागपुर क्षेत्र), खैराहा भूमिगत खदान (सोहागपुर क्षेत्र), बेहराबांध भूमिगत खदान (जोहिला क्षेत्र), विजय वेस्ट भूमिगत खदान (हसदेव क्षेत्र) तथा जगन्नाथपुर ओपनकास्ट परियोजना को इस वर्ष 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली एसईसीएल की एकमात्र ओपनकास्ट परियोजना है, ने ओवरबर्डन प्रबंधन, हरित विकास, जल संरक्षण एवं सुरक्षित उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों दर्ज की हैं। इस उपलब्धि पर एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुहन ने कहा, एसईसीएल की पाँच खदानों को एक साथ 5-स्टार रेटिंग मिलना पूरे एसईसीएल परिवार के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। यह उपलब्धि कोयला एवं लिग्नाइट खदानों के प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन करती है। इसके अंतर्गत सुरक्षित एवं वैज्ञानिक खनन, पर्यावरण संरक्षण, भूमि पुनर्वास, आधुनिक

तकनीकों का उपयोग, श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण, वैधानिक अनुपालन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा परिचालन दक्षता जैसे विभिन्न मानकों पर खदानों का आकलन किया जाता है। इन सभी मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खदानों को ही सर्वोच्च 5-स्टार रेटिंग प्रदान की जाती है। इस वर्ष 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली एसईसीएल की बंगवार, खैराहा, बेहराबांध एवं विजय वेस्ट भूमिगत खदानों ने सुरक्षित खनन, वैज्ञानिक खनन, उत्पादन दक्षता, श्रमिक कल्याण तथा पर्यावरणीय प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं जगन्नाथपुर ओपनकास्ट परियोजना, जो इस वर्ष 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली एसईसीएल की एकमात्र ओपनकास्ट परियोजना है, ने ओवरबर्डन प्रबंधन, हरित विकास, जल संरक्षण एवं सुरक्षित उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों दर्ज की हैं। इस उपलब्धि पर एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुहन ने कहा, एसईसीएल की पाँच खदानों को एक साथ 5-स्टार रेटिंग मिलना पूरे एसईसीएल परिवार के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। यह उपलब्धि कोयला एवं लिग्नाइट खदानों के प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन करती है। इसके अंतर्गत सुरक्षित एवं वैज्ञानिक खनन, पर्यावरण संरक्षण, भूमि पुनर्वास, आधुनिक

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी ने की 47 प्रकरणों की सुनवाई

**बिलासपुर।** छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक एवं प्रभारी सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया ने आज जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जन सुनवाई की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर 411 एवं जिला में 23 वां जन सुनवाई हुई। आज की जनसुनवाई में प्रकरण संख्या 47 है। अन्य प्रकरण में आवेदिकागण, अनावेदक की पुत्री है उन्होंने बताया कि उनके पिता मेडिकल में काम करते हैं व 14 वर्ष से अलग रहते हैं। आवेदिका के माता को फर्नी केस में फंसाने की धमकी देते थे पर की छत्र में 3000 नग की नशीली दवा रखकर उसकी मां को पसया गया है। मां के उपर एनडीपीएस का

मामला बन गया है वह छः माह से जेल में है। आवेदिकागण ने बताया कि अनावेदक का श्री राममेडिकल अशोकनगर सरकण्डा में है जिसे अनावेदक ने स्वीकार किया कि वह दूसरे के लायसेंस से मेडिकल स्टोर चलाता था व 2022 ये भाँचा के नाम पर 300000 रुपये में बेचा व स्वयं उस दुकान का काम करता है व उसका तनख्वाहा 10000/- रुपये है जिससे वह पूर्व में न्यायालय के आदेश से 2014 से 2026 फरवरी तक दे रहा था व 2026 फरवरी से भरणपोषण नहीं दे रहा है। इससे स्पष्ट है कि अनावेदक भरणपोषण देने से बचने के लिए फर्नी बिक्रीनामा किया है ताकि आवेदिका को भरणपोषण से बच सकें। आवेदिकागण ने यह भी बताया कि अनावेदक उनके पिता 2006 से मेडिकल का काम कर रहे हैं व 2013 से स्वतंत्र मेडिकल स्टोर है। वर्तमान



में भी मेडिकल स्टोर का कार्य कर रहे हैं जिससे यह स्पष्ट है कि अपनी पत्नी को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी थी उसके तहत 3000 हजार नशे की टेबलेट रखवाकर झूठे फंसाया है। चूंकि इस मामले में अनावेदक का 20 साल का सेवा अनुभव है कि कौन सा टेबलेट कहा मिलता है उसका उपयोग क्या होता है। आवेदिकागण ने

बताया कि अनावेदक ने अपने ही मेडिकल स्टोर में बैठने वाली लड़की से विवाह कर लिया है व अनावेदक के द्वारा पड़ोसी को मैसेज किया है कि आवेदिका उससे तलाक ले ले। उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया गया है। उपस्थित एडिशनल एसपी रश्मिंत कौर चावला ने सरकण्डा थाना से दिनांक 15.02.2026 को एफआई.आर. की कापी

दिलाई व बताया कि यह सब दवाईयां आरोपी के यहाँ से जब है यह सूचना मुखविर के माध्यम से मिली थी जो दवाईयां जब की उस दवाईयां के बेज नं. से पुलिस ने पता नहीं किया कि किस डीलर को बेचा गया है। वहाँ से आवेदिका को कैस मिला उसका स्पष्टीकरण एफआई.आर. में नहीं है। व अनावेदक ने अपने दस्तावेज दिया है कि उसने 114000 रुपये की सम्पूर्ण राशि आवेदिकागण को दिया है व मामला नस्टीबद्ध हो गया है व अदालत की तारीख 24.06.2026 अंकित है जब कि आवेदिका की मां इस दिनांक को जेल में थी जिसे आवेदिका इस राशि को कब प्राप्त की यह अंकित नहीं है। अर्थात अनावेदक लगातार अपने दोनो बेटों को भरण पोषण देने से बचने अपनी पत्नी को झूठे एनडीपीएस मामले में फंसाया दिखता है।

# रसोई घर में भूलकर भी न करें ये वास्तु गलतियां

वास्तु शास्त्र में रसोई घर को केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा और समृद्धि का केंद्र माना गया है। मान्यता है कि रसोई में तैयार होने वाला अन्न पूरे परिवार के स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और आर्थिक उन्नति को प्रभावित करता है। इसलिए रसोई की स्वच्छता, व्यवस्था और दिशा का विशेष महत्व बताया गया है। यदि अनजाने में कुछ वास्तु संबंधी गलतियां लगाए जाएं, तो घर में बरकत और सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। आइए जानते हैं रसोई पांच प्रमुख गलतियों के बारे में, जिनसे बचना शुभ माना गया है।



## 1. रसोई में गंदे बर्तन रातभर छोड़ देना

वास्तु मान्यता के अनुसार रातभर जुटे बर्तन सिक के पड़े रहने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा करने से घर में आलस्य बढ़ सकता है और आर्थिक उन्नति में बाधाएं आने की संभावना मानी जाती है। इसलिए भोजन के बाद यथासंभव बर्तन साफ करके ही सोना बेहतर माना गया है। इससे रसोई में स्वच्छता और सकारात्मक वातावरण बना रहता है।

## 2. चूल्हा और पानी का स्रोत एकदम साथ रखना

रसोई में अग्नि और जल दो विपरीत तत्व माने गए हैं। यदि गैस चूल्हा और सिंक बिल्कुल साथ-साथ हों, तो वास्तु के अनुसार इन दोनों तत्वों का असंतुलन घर के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। यदि मजबूरी में ऐसा हो, तो इनके बीच थोड़ा स्थान रखें या लकड़ी का छोटा पार्टिशन अथवा हरे रंग की कोई वस्तु रखकर संतुलन बनाने का प्रयास किया जा सकता है।

## 3. रसोई में अनाज के डिब्बे खाली रखना

वास्तु शास्त्र में अन्न को माता अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है। इसलिए घर में अनाज के डिब्बे पूरी तरह खाली रखना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि इससे धन और अन्न की कमी का संकेत मिलता है। कोशिश करें कि चावल, आटा, दाल या अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री के पात्र कभी पूरी तरह खाली न रहें।

## 4. टूटे-फूटे बर्तन और खराब सामान संभालकर रखना

बहुत से लोग पुराने या टूटे हुए बर्तन सह सोकर संभालकर रखते हैं कि भविष्य में काम आ जाएंगे। लेकिन वास्तु के अनुसार टूटे बर्तन, चटके हुए कप या बेकार रसोई उपकरण नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ऐसे सामान को समय पर घर से हटाना और केवल उपयोगी वस्तुएं ही रसोई में रखना शुभ माना गया है।

## 5. रसोई की नियमित सफाई और रोशनी की अनदेखी करना

रसोई हमेशा साफ, हवादार और पर्याप्त रोशनी वाली होनी चाहिए। कोनों में जमी गंदगी, जाले या नमी को वास्तु में शुभ नहीं माना गया है। माना जाता है कि स्वच्छ और प्रकाशयुक्त रसोई में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, जिससे परिवार में सुख-शांति और समृद्धि का वातावरण विकसित होता है।

# नमक और लौंग से दूर होगी नकारात्मकता

आज के समय में हर व्यक्ति बेहतर जीवन जीने की इच्छा रखता है और इसके लिए अच्छी आय होना जरूरी माना जाता है। हालांकि कई बार लोग पर्याप्त कमाई करने के बावजूद यह महसूस करते हैं कि उनके पास धन ठिक नहीं पाता या

बार-बार आर्थिक समस्याएं सामने आती रहती हैं। वास्तु शास्त्र में ऐसे हालात के लिए कुछ सरल उपाय बताए गए हैं, जिनमें नमक और लौंग से जुड़ा उपाय भी शामिल है। इसे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और समृद्धि लाने में सहायक माना जाता है।

## नमक और लौंग का महत्व

वास्तु के अनुसार घर की ऊर्जा सही तौर पर वहां रहने वाले लोगों के जीवन, सुख-शांति और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में मदद करता है, जबकि लौंग की खुशबू वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखने का प्रतीक होती है।

## इस तरह करें उपाय

इस उपाय को करने के लिए एक कांच की कटोरी लें और उसमें थोड़ा मोटा नमक भर दें। इसके बाद उसमें चार या पांच लौंग डालकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें, जहां वह सुरक्षित और स्थिर रह सके। बहुत से लोग इस उपाय को घर का माहौल बेहतर बनाए रखने के लिए अपनाते हैं।

## क्या कहती है मान्यता

वास्तु मान्यताओं के अनुसार इस उपाय से घर में नकारात्मकता कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। माना जाता है कि इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है, धन का प्रवाह बढ़ सकता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। इसके अलावा लौंग की हल्की सुगंध से घर का वातावरण भी ताजगी भरा महसूस होता है।

## बाथरूम से जुड़ा उपाय

यदि बाथरूम में किसी प्रकार का वास्तु दोष माना जाता है, तो वहां एक कटोरी में सोचा या क्रिस्टल नमक भरकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही समय-समय पर इस नमक को बदलते रहना चाहिए। मान्यता है कि इससे उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और वातावरण संतुलित बना रहता है।



# पुदीने को लंबे समय तक ताजा रखने के उपाय



घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों की मदद से आप पुदीने की ताजगी और खुशबू लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। अगर आप भी बार-बार पुदीना खरीदने से परेशान हैं या चाहते हैं कि आपकी घटनी और डिब्बे में हमेशा ताजा पुदीना इस्तेमाल हो, तो ये आसान और असरदार टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं।

तो उसकी डंठियों को पानी से भरे ग्लास या जार में रखें। यह तरीका फूलों को ताजा रखने जैसा ही है। जार को फ्रिज में रखें और हर दो दिन में पानी बदलते रहें। इससे पुदीने की पत्तियां लंबे समय तक हरी और फ्रेश बनी रहती हैं।

**फ्रीजर में स्टोर करें**  
अगर आपको पुदीने का उपयोग रोज नहीं करना है, तो फ्रीजर एक बेहतरीन विकल्प है। पत्तियों को अलग करके आइस ट्रे में रखें और ऊपर से पानी डालकर फ्रीज कर दें। जरूरत पड़ने पर इन क्यूब्स को थ्रिक्स, चटनी या अन्य व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पुदीने का स्वाद और खुशबू काफी हद तक बरकरार रहती है।

**इन गलतियों से बचें**  
पुदीने को कभी भी गीली पॉलीथिन में बंद करके न रखें। साथ ही इसे फ्रिज के ऐसे हिस्से में न रखें जहां तापमान बहुत कम हो। ज्यादा नमी और अत्यधिक ठंड दोनों ही पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा खराब या पीली पत्तियों को पहले ही अलग कर दें, क्योंकि वे बाकी पत्तियों को भी जल्दी खराब कर सकती हैं।

# आज का राशिफल

**मेष राशि** - स्वास्थ्य में माता का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी। कल आप किसी बड़े निर्णय को लेने में सक्षम होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यक्षमता को सराहा जाएगा और आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा।

**वृषभ राशि** - मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी। कल का दिन नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी पुराने मित्र से मिल सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

**मिथुन राशि** - आर्थिक लाभ और आय में वृद्धि के संकेत हैं। शिक्षा, तकनीक और निवेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों बढ़ सकती हैं, लेकिन सहयोग भी प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से गले या आंखों का थोड़ा ध्यान रखें। धन संबंधी मामलों में बहुत सतर्क रहें और सोच-समझकर ही पैसा खर्च करें।

**कर्क राशि** - घर और कार्यक्षेत्र दोनों में संतुलन बनाने का अवसर मिलेगा। मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी। प्रेम संबंधों में कुछ तनाव संभव है, इसलिए संवाद बनाए रखें। तब लाइफ में साथी के साथ रोमांटिक पल व्यतीत करेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप मन से भी काफी प्रसन्न रहेंगे। कल आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहेगा।

**सिंह राशि** - भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में लाभ के अवसर बनेंगे। परिवार, बच्चों की शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लव लाइफ में साथी के साथ थोड़ा दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए बातचीत जारी रखें। आध्यात्मिक कार्यों या योग-ध्यान में रुचि लेने से मन को शांति प्राप्त होगी।

**कन्या राशि** - अचानक धन लाभ या रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। छात्रों और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। और आप भविष्य की सुखद योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आप अपने मित्रों के साथ एक खुशनुमा दिन बिताएंगे।

**तुला राशि** - दौलतप्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। संपत्ति, निवेश और व्यापक साधक सौंदर्य में लाभ के योग हैं। बुद्धिमानों से लिए गए निर्णय आपको सफलता दिलाएंगे। आपके पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लव लाइफ में साथी के साथ तालमेल बहुत ही सुंदर रहेगा और आपसी प्रेम गहरा होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा है, ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा।

**सुरिचक राशि** - करियर संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। वाहन सुख और सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। आपका मन शांत रहेगा, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। मेहनत का सकारात्मक फल मिलेगा।

**धनु राशि** - विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा और कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। लव लाइफ में साथी की सहेत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, उनका ध्यान रखें। स्वास्थ्य में पैट या पाचन से जुड़ी समस्याओं के प्रति सचेत रहें और हल्का भोजन लें।

**मकर राशि** - पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभ पहुंचा सकती है। नौकरी में बदलाव पर विचार कर सकते हैं। आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य है, बस नियमित खान-पान का ध्यान रखें। कल आप अपने कार्यों के प्रति काफी सजग रहेंगे।

**कुंभ राशि** - सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं। परिवार और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आप नई स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। रोगों और शत्रुओं पर विजय दिलाने में मददगार साबित होगा।

**मीन राशि** - मेहनत का फल मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। घर में शुभ कार्य का आयोजन संभव है। छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने की सलाह दी जाती है। आपके रचनात्मक विचारों की प्रशंसा होगी। किजनेस में कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, बशर्त आप सही योजना बनाएं।

**मेष राशि** - स्वास्थ्य में माता का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी। कल आप किसी बड़े निर्णय को लेने में सक्षम होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यक्षमता को सराहा जाएगा और आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा।

**वृषभ राशि** - मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी। कल का दिन नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी पुराने मित्र से मिल सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

## पुदीने को धोने के बाद पूरी तरह सुखाएं

अधिकतर लोग पुदीना चोकर सीधे फ्रिज में रख देते हैं, जिससे उसमें नमी बनी रहती है और पत्तियां जल्दी खराब होने लगती हैं। पुदीने को धोने के बाद किसी सूती कपड़े या किचन टॉवल पर फैलाकर अच्छी तरह सुखा लें। जब पत्तियों पर बिल्कुल भी पानी न रहे, तभी उसे स्टोर करें। यह तरीका पुदीने की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद करता है।

## टिशू पेपर में लपेटकर रखें

पुदीने को लंबे समय तक ताजा रखने का सबसे लोकप्रिय तरीका है उसे टिशू पेपर में लपेटना। टिशू अतिरिक्त नमी को सोख लेता है और पत्तियों को सूझने से बचाता है। पुदीने को हल्के से टिशू में लपेटकर एयरटाइट डिब्बे या जिप लॉक बैग में रख दें। इससे पुदीना 10 से 15 दिनों तक ताजा रह सकता है।

## पानी वाले जार में स्टोर करें

अगर आप पुदीने को बिल्कुल ताजा रखना चाहते हैं,

# बच्चे की मालिश करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां

अक्सर बच्चों की मालिश करना उनकी सेहत और विकास के लिए बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इससे उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर खिंचवट रहता है और नींद भी बेहतर होती है। भारत में यह परंपरा लंबे समय से अपनई जाती रही है। लेकिन गर्मियों के मौसम में मालिश करते समय थोड़ी सी लापरवाही भी बच्चे की त्वचा और सेहत पर असर डाल सकती है। डॉक्टरों के अनुसार, इस दौरान कुछ खास गलतियों से बचना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसी 6 आम गलतियां, जो गर्मियों में बच्चे की मालिश करते समय कभी नहीं करनी चाहिए।



## घूप वाले कमरे में मालिश करना

बच्चे की मालिश कभी भी गर्म या घूप वाले कमरे में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा असहज महसूस कर सकता है और उसे पसीना या परेशानी हो सकती है। मालिश हमेशा ऐसे कमरे में करें जो ठंडा, साफ और अच्छी तरह हवादार हो, ताकि बच्चा पूरी तरह आरामदायक महसूस करे और उसकी त्वचा पर भी कोई नकारात्मक असर न पड़े।

## बहुत टाइट या जोर से मालिश करना

बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसलिए बहुत टाइट या जोर से मालिश करना बिल्कुल सही नहीं है। जोर-जबरदस्ती या सख्त मालिश करने से बच्चा असहज महसूस कर सकता है और रोने भी लगता है। हमेशा हल्के, सॉफ्ट और जेटल हाथों से ही मालिश करनी चाहिए, ताकि बच्चा आराम महसूस करे और उसे किसी तरह की परेशानी न हो।

## चिपचिपे और भारी तेल का इस्तेमाल

गर्मियों में चिपचिपे और भारी तेल का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की त्वचा पर रेशेज और असहजता हो सकती है। खासतौर पर सरसों जैसे भारी तेल को इस मौसम में अवॉइड करना बेहतर होता है। इसके बजाय नारियल तेल या बादाम तेल जैसे हल्के तेल का इस्तेमाल करें और यह भी बहुत कम मात्रा में, ताकि बच्चे की त्वचा सुरक्षित और आरामदायक बनी रहे।

## सही मालिश क्यों जरूरी है?

सही तरीके से की गई मालिश बच्चे को रिलेक्स करती है, नींद बेहतर बनाती है और माता-पिता और बच्चे के बीच बॉन्डिंग को मजबूत करती है। गर्मियों में बच्चों की मालिश करते समय थोड़ी सावधानी बहुत जरूरी है। सही तरीका अपनाकर आप बच्चे को स्वस्थ, आरामदायक और खुश रख सकते हैं।

# मानसून से पहले स्किन और बालों की तैयारी कैसे करें?

मानसून का मौसम अंदर एक लफ्फे गर्मी से राहत लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ स्किन और बालों से जुड़ी कई समस्याएं भी साथ लाता है। बदती नमी, पर्याप्त और गंदगी के कारण त्वचा पर पिंपल्स, ऑयली स्किन और फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं बालों में ड्रफ, हेयर फॉल और स्कोल्प इन्फेक्शन की समस्याएं भी आम हो जाती हैं। अक्सर लोग मानसून आने के बाद अपनी स्किन केयर रूटीन में बदलाव करते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सही तैयारी बरिस्टा शुरू होने से पहले ही कर लेनी चाहिए।



यदि पहले से सही स्किन और हेयर केयर अपनाया जाए, तो कई परेशानियों से आसानी से बचा जा सकता है। इस मौसम में त्वचा और बाल दोनों अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, इसलिए हल्के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, सही साफ-सफाई और हल्की लाइफस्टाइल बेहद जरूरी हो जाती है। थोड़ी-सी सावधानी आपकी स्किन को नोडों और बालों को मजबूत बनाए रख सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस मानसून आपकी स्किन और बाल हमेशा हेल्दी और फ्रेश दिवें, तो नीचे दिए गए टिप्स आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे।

■ **स्किन को हल्का और क्लीन रखें**  
मानसून से पहले स्किन केयर रूटीन को सरल बनाएं। दिन में दो बार माइल्ड फेस वॉश से चेहरा साफ करें। इससे अतिरिक्त ऑयल और गंदगी हटा जाती है। भारी क्रीम की जगह हल्के जेल-बेस मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें।  
■ **पिंपल्स और ऑयली स्किन से बचाव**  
नमी बढ़ने पर त्वचा अधिक ऑयली हो जाती है, जिससे पिंपल्स बढ़ सकते हैं। सैलिसेलिक एसिड या टी-टी ऑयल युक्त प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मदद कर सकता है।  
■ **बालों को नियमित वॉश करें**  
मानसून से पहले बालों की साफ-सफाई बहुत जरूरी है। सप्ताह में 2-3 बार माइल्ड शैम्पू से बाल धोएं। इससे स्कैल्प पर जमा गंदगी और ऑयल कम होगा। बार-बार चेहरे को छूने से बचें।  
■ **ड्रैफ कंट्रोल पर ध्यान दें**  
नमी के कारण ड्रैफ की समस्या बढ़ सकती है। एंटी-ड्रैफ शैम्पू का उपयोग करें और बालों को हमेशा सूखा रखें। गीले बालों में लंबे समय तक न रहें।



**शिवनाथ का तेवर**

दो दिन की बारिश में दुर्ग शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जिससे महमरा एनीकट के ऊपर से पानी बह रहा है। जिसके चलते महमरा गांव तरफ के आवागमन को स्टॉपर लगाकर बंद कर दिया गया है। सासाह भर से ग्रामीण दुर्ग राजनंदगांव मार्ग से आवागमन कर रहे हैं।  
फोटो : नाहीद शेख

**नहीं बना मगरघटा-परसदा पुल, हाई स्कूल में बच्चों के प्रवेश पर पड़ा असर**

अम्लेश्वर/पाटन। नगर पालिका परिषद कुम्हारी एवं नगर पालिका परिषद अम्लेश्वर क्षेत्र को जोड़ने वाली मगरघटा-परसदा पुलिया का निर्माण पिछले कई वर्षों से अधर में लटक हुआ है। जुलाई 2023 में इस पुल के निर्माण को प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रवासियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सूत्रों के अनुसार नगर पालिका परिषद अम्लेश्वर के वार्ड क्रमांक 15 मगरघटा की पार्श्व यामिनी मनोज यादव ने इस संबंध में ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि 20 जुलाई 2023 को पुल निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा निविदा प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई है, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल का निर्माण नहीं होने से मगरघटा और परसदा के विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। परसदा में हाई स्कूल की स्वीकृति मिलने के



बाद भी मगरघटा के अभिभावक अपने बच्चों का वहां प्रवेश करने से बच रहे हैं। बारिश के दिनों में नाले पर बने एप्रोच मार्ग के ऊपर से पानी बहने लगता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और विद्यार्थियों का आवागमन बाधित हो जाता है। यदि दूसरे मार्ग से जाना पड़े तो लगभग 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। विद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष मगरघटा के 19 विद्यार्थियों का परसदा हाई स्कूल में प्रवेश प्रस्तावित था, लेकिन केवल 4 विद्यार्थियों ने ही प्रवेश लिया। वहीं 8 विद्यार्थियों ने

स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) लेकर अम्लेश्वर के हारर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश ले लिया है, जबकि 7 विद्यार्थियों ने अभी तक किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है। इससे अभिभावकों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मगरघटा-परसदा पुल का निर्माण नहीं होगा, तब तक वे अपने बच्चों को परसदा हाई स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि बच्चे या तो अम्लेश्वर के विद्यालयों में प्रवेश लेंगे या फिर शिक्षा से वंचित होने की स्थिति पैदा हो सकती है।

**अंबिकापुर एनएच गोयल हॉस्पिटल में बड़ा फर्जीवाड़ा : आयुष्मान योजना में पंजीयन के बिना मरीजों को भर्ती करने का आरोप**

**संभागीय संयुक्त संचालक ने दिए विस्तृत जांच के निर्देश; जिला कलेक्टर को लिखा पत्र, लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी**

अंबिकापुर, 9 जुलाई/ अंबिकापुर के एनएच गोयल हॉस्पिटल के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में एक बेहद गंभीर मामला उजागर हुआ है। अस्पताल पर आरोप है कि आयुष्मान भारत योजना में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) न होने के बावजूद, वहां मरीजों को इस योजना के नाम पर भर्ती किया गया और कथित रूप से अवैध लाभ उठवाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक डॉ. अनिल कुमार शुक्ला ने विस्तृत जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने दोषी पाए जाने पर अस्पताल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं।  
सीएमएचओ की रिपोर्ट में खुलासा- संभागीय संयुक्त संचालक डॉ. अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि शिकायत मिलने पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को



डॉ. अनिल कुमार शुक्ला संभागीय संयुक्त संचालक

मामले की जांच सौंपी थी। 6 जुलाई को सौंपे गए सीएमएचओ की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि एनएच गोयल हॉस्पिटल का आयुष्मान भारत योजना के तहत कोई पंजीयन ही नहीं है। डॉ. शुक्ला ने सवाल उठाया कि बिना वैध पंजीयन के अस्पताल प्रबंधन ने आयुष्मान योजना

के नाम पर मरीजों को भर्ती कैसे किया, इसकी गहनता से जांच की जाएगी।  
अवैध वसूली और राशि आहरण पर होगी सख्त कार्रवाई- स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है कि अस्पताल ने आयुष्मान योजना के नाम पर फर्जी तरीके से सरकारी राशि निकाली है या मरीजों से अवैध वसूली की है, तो इसे गंभीर अनियमितता माना जाएगा। संभागीय संयुक्त संचालक ने मामले में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को भी एक आधिकारिक पत्र भेजा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आरोप सिद्ध होने पर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने सहित अन्य दंडात्मक कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।  
आरटीआई एक्टिविस्ट दर्ज कराएंगे एफआईआर- इस पूरे मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ. शैके सोनी ने

भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन मरीजों को घोखे में रखकर आयुष्मान योजना का कथित लाभ उठाना एक बड़ा अपराध है। वे इस फर्जीवाड़े को लेकर संबंधित अस्पताल संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं।  
जिले के सभी निजी अस्पतालों को चेतावनी- इस बड़े खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। संभागीय संयुक्त संचालक ने जिले के सभी निजी अस्पतालों को सख्त हिदायत दी है कि वे आयुष्मान भारत योजना के तय नियमों और गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें। नियमों की अनदेखी या किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

**अल नीनो के असर को लेकर कृषि विभाग अलर्ट, किसानों के लिए जारी हुई विशेष एडवाइजरी**

दुर्ग। इस वर्ष अल-नीनो के चलते मानसून में देरी, खंड वर्षा (लंबे समय तक सूखा) और सीजन के जल्दी समाप्त होने की गंभीर आशंका बनी हुई है। इस संभावित संकट से निपटने और किसानों की आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए कृषि विभाग द्वारा एक विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जोखिम को कम करने के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, कम पानी वाली फसलों का चयन, जल संरक्षण और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से सीमित संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करना है। उप संचालक कृषि संदीप भोई ने बताया कि कार्यक्रम अगस्त-सितंबर किसान भाई मौसम की अनिश्चितता से बचने के लिए कम पानी और कम अर्वाध में तैयार होने वाली धान की उन्नत किस्में को अपनाए। इसके साथ ही, टिकार और भर्रा जैसी ऊंची तथा ढलान वाली भूमियों पर जल संरक्षण और समबद्ध बुआई



सुनिश्चित करने के लिए कतारबद्ध सीधी बुआई यानी डीएसआर पद्धति को अपनाए। जोखिम को कम करने के लिए किसी एक फसल (जैसे धान) पर पूरी तरह निर्भर न रहें फसल विविधीकरण अपनाएं। धान के बदले कम पानी में होने वाली दलहन फसल जैसे अरहर, मूंग एवं उड़द तथा तिलहन फसल जैसे तिल, सोयाबीन, मूंगफली को प्राथमिकता दें। फसलों की सुरक्षा के साथ-साथ खेतों की मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए रभूमि आच्छन्नदण्ड (मलचिंग) तकनीक अपनाए जिससे तहत फसल बोने से पहले और कटाई के बाद खेतों को ढँका अथवा दलहन फसलों से ढका जाएगा।

**स्व. संतोष यादव की सुपुत्री की शिक्षा के लिए फिर बड़ा सहयोग का हाथ, सर्व समाज कल्याण समिति ने दिए 35 हजार**

भिलाई। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय संतोष यादव की सुपुत्री की शिक्षा में सहयोग के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सर्व समाज कल्याण समिति, भिलाई के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने लगातार दूसरे वर्ष परिवार को 35,000 की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि बेटी की शिक्षा और उज्वल भविष्य के लिए समिति का सहयोग आगे भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि स्व. संतोष यादव के निधन के बाद उनकी सुपुत्री की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए इंद्रजीत सिंह ने परिवार से हरसंभव सहयोग का वचन दिया था। उसी संकल्प को निभाते हुए यह आर्थिक सहायता प्रदान की गई। समिति द्वारा पूर्व वर्ष भी शिक्षा सहायता के रूप में सहयोग राशि उपलब्ध कराई गई थी। इस अवसर पर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि शिक्षा किसी भी बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। समाज के



प्रत्येक सक्षम व्यक्ति और संस्था का यह नैतिक दायित्व है कि कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे परिवारों के बच्चों की शिक्षा में सहयोग करें। उन्होंने कहा, स्वर्गीय संतोष यादव जी पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम थे। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हमेशा जुड़ी रहेंगी। हमारी कोशिश है कि उनकी सुपुत्री अपनी शिक्षा बिना किसी बाधा के पूरी कर सकें और जीवन में अपने सपनों को साकार करें। समाज तभी मजबूत बनेगा जब हम जरूरतमंद परिवारों के साथ खड़े

**जसम दुर्ग-भिलाई इकाई का पुनर्गठन: अशोक तिवारी अध्यक्ष, सुरेश वाहने फिर बने सचिव**

भिलाई। जन संस्कृति मंच (जसम) दुर्ग-भिलाई इकाई की महत्वपूर्ण बैठक इस्पात नगर भिलाई में आयोजित की गई, जिसमें संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया संपन्न हुई। बैठक में जन संस्कृति मंच छत्तीसगढ़ के संरक्षक-समन्वयक सियाराम शर्मा, प्रसिद्ध कथाकार कैलाश बनवासी, जसम के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सोनी, छत्तीसगढ़ राज्य इकाई की अध्यक्ष रूपेन्द्र तिवारी तथा कार्यकारिणी सदस्य पूनम संजु विशेष रूप से उपस्थित की बैठक में सर्वसम्मति से वरिष्ठ आलोचक अशोक तिवारी को जन संस्कृति मंच दुर्ग-भिलाई इकाई का अध्यक्ष चुना गया, जबकि लेखक सुरेश वाहने को लगातार दूसरी बार सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। नई कार्यकारिणी के गठन के साथ संगठन को अधिक सक्रिय और व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नई कार्यकारिणी में एन. पापा राव, दिव्या और विद्याभूषण को उपाध्यक्ष बनाया गया है। सुबोध देवांगन एवं



पूणिमा साहू को सह-सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सुलेमान खान को कोषाध्यक्ष तथा अनु वर्मा को सह-कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाट्य गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी संस्कृतिकर्म हरजिंदर सिंह मोटिया और जयप्रकाश नायर को सौंपी गई है। कार्यकारिणी सदस्यों में मीतादास, घनश्याम त्रिपाठी, अंजन कुमार, अभिषेक पटेल, बुजेंद्र तिवारी, दिनेश सोलंकी, टेकलाल निराला, पवन कुमार छिटे और मनिंदर सिंह को शामिल किया गया है। संगठन के संरक्षक मंडल में सियाराम शर्मा, कैलाश बनवासी तथा कवि वासुकि प्रसाद 'उमठत' को जिम्मेदारी प्रदान की गई है। बैठक को संबोधित करते हुए सियाराम शर्मा ने जन संस्कृति मंच के सांस्कृतिक इतिहास, उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक आंदोलनों में उसकी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को जनशक्ति से संपन्न और सक्रिय बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सोनी ने संगठन में युवाओं की भागीदारी को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि सांस्कृतिक आंदोलनों को नई ऊर्जा और नए नेतृत्व की जरूरत है।

**जिले का पहला अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम अम्बेडकर नगर में होगा शुरू, 24 घंटे मिलेगी अपने राशनकार्ड का चावल**

**कलेक्टर अभिजीत सिंह ने किया अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम का निरीक्षण**

दुर्ग। जिले का पहला अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम सुपेला के गदा चौक स्थित अम्बेडकर नगर में शुरू होने जा रहा है। इस अत्याधुनिक व्यवस्था के माध्यम से राशनकार्डधारी अब 24 घंटे अपनी सुविधा अनुसार चावल प्राप्त कर सकेंगे। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम का निरीक्षण कर शुभारंभ की तैयारियों का जायजा लिया तथा सुरक्षा एवं संचालन के लिए चौकीदार और ऑपरेटर की दो शिफ्ट में इयूटी लगाने के निर्देश दिए। वन नेशन, वन राशनकार्ड योजना के तहत राशनकार्डधारी, चाहे वह जिले के किसी भी क्षेत्र में निवास करता हो या किसी भी उच्च मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करता हो, अम्बेडकर नगर



स्थित इस ग्रीन एटीएम से अपने हिस्से का चावल प्राप्त कर सकेंगे। अन्नपूर्ति ग्रीन एटीएम का संचालन महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। समूह की सदस्य मशीन में चावल की आपूर्ति, संचालन एवं

हितग्राहियों की सहायता के लिए उपस्थित रहेंगी। वहीं इच्छुक हितग्राही स्वयं भी मशीन का उपयोग कर चावल प्राप्त कर सकेंगे। एटीएम की क्षमता 2.7 मीट्रिक टन है। इस व्यवस्था से लोगों को उच्चतम मूल्य

की दुकानों पर लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और राशन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज एवं सुविधाजनक बनेगी। मशीन से चावल प्राप्त करने के लिए हितग्राही को सबसे पहले अपना राशनकार्ड नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन (अंगूठे का निशान) करना होगा। सत्यापन पूर्ण होते ही पात्रता के अनुसार निर्धारित मात्रा में चावल मशीन से स्वतः उपलब्ध हो जाएगा। केवल शासन द्वारा जारी वैध राशनकार्डधारियों को ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इस दौरान खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया सहित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

**वार्ड 50 और 53 में विकास कार्यों की सौगात, महापौर ने नागरिकों के साथ किया भूमिपूजन**

**12.50 लाख की लागत से आरसीसी नाली-फुलिया एवं 5 लाख से बनेगा सिव मंदिर स्थित मंच, नागरिकों ने जताया आभार**

दुर्ग। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्यों को गति देते हुए महापौर अलका बाघमार ने वार्ड क्रमांक 50 एवं 53 में विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, वार्ड 50 पार्श्व रेखा बंजारे, वार्ड 53 पार्श्व सविता साहू, रंजीता पाटिल, सहायक अभियंता हरिशंकर साहू, ज्ञानदास बंजारे, अभितेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में वार्ड के नागरिक उपस्थित रहे। महापौर अलका बाघमार द्वारा वार्ड क्रमांक 50 बोरसी भाटा-पूर्व क्षेत्र में एलआईजी 154 से 142 एवं 192 से 199 तथा बंशी विहार गली नंबर-1 में डी. बरवा के घर से चौरसिया घर तक आरसीसी नाली एवं फुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। उक्त निर्माण कार्य की लागत राशि 12.50 लाख रुपये है। इसी क्रम में वार्ड



क्रमांक 53 मिनाश्री नगर स्थित शिव मंदिर के सामने महापौर निधि से स्वीकृत 5 लाख रुपये की लागत से बने वाले मंच निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन किया गया। भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान वार्डवासियों ने क्षेत्र में विकास कार्यों की स्वीकृति एवं

शुरुआत के लिए महापौर अलका बाघमार का आभार व्यक्त किया। महापौर ने नागरिकों से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। सड़क, नाली, फुलिया सहित आवश्यक विकास कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।